COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTEENTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move:

> "That this House agrees with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 11th March, 1958.".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 11th March, 1958.".

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE* EXTENSION OF PERIOD OF RESERVATION OF SEATS IN LEGISLATURES FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री दीनबन्धु परमार (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प पेश करता हूं कि इस सभा की यह राय है कि सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए विधान प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अन्तर्गत संसद् और विधान-मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उपबन्धित स्थानों के रक्षण की अवधि दस वर्ष और बढ़ा दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ज़रा ठहर जायें। यह रेजोल्यूशन अब मूव तो हो गया और अब मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस पर तकरीर भी करें, लेकिन चूंकि मुझ पर यह बोझ है, इसलिए मैं पहले वक्त के मुताल्लिक फैसला कर देना चाहता हूं। जितनी चिट्स मेरे पास आ रही हैं, उनसे मालूम होता है कि शायद इस मजमून पर सारे ही मेम्बर साहबान बोलना चाहेंगे। इसलिए मैं शुरू में ही यह कहना चाहता हूं कि हरेक सदस्य यह ख्याल रखे और कम से कम वक्त ले, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा मेम्बर बोल सकें, उतना ही अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य : दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे तो दस मिनट रखने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर दस मिनट रखे जायेंगे, तो बहुत थोड़े मेम्बर साहबान बोल सकेंगे। अगर दस मिनट से भी कम—सात मिनट—रखें जायें, तो ठीक होगा।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सात मिनट ही कर दिए जायें। सबको मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक मेम्बर साहब के लिए सात मिनट हैं और जिन्होंने मूव किया है, उनके लिए पंद्रह मिनट रखे जाते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : (फिरोजाबाद): समय कितना है?

उपाध्यक्ष महोदय : २ घंटे २६ मिनट।

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Why not extend the time?

Shri B. K. Gaikwad (Nasik): The resolution is very important, and, therefore, the time may please be extended. If Members want to express their views, they should be allowed to speak.

Shri Thimmaiah (Kolar—Reserved-Sch. Castes): We may extend the time up to 6 P.M.

Mr. Deputy-Speaker: The difficulty is that hon. Members do not take up the question when there is the opportunity for them. When I was putting the motion before the House and it was being voted upon by the House nobody stood up and said that the time

[Mr. Deputy-Speaker]

allotted was too small. Now, immediately after one minute when the House has voted on it and given its approval, they say that more time should be given. Would the House like to alter its decision one minute after it has taken that decision?

Shri Tangamani (Madurai): 2 hours and 29 minutes were fixed so as to enable the second resolution also to be moved. So, if more than 2 hours and 29 minutes are given to this resolution, then the second resolution will be elbowed out.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, certainly. That was the real reason for allotting this much time. But if there was a demand for more time, and hon. Members thought that time should be extended, then in that case, when I put the motion to vote, they should have raised that; when I put the motion, I looked round, but nobody stood up to say that. What could I have done in that case?

श्री दीनबन्धु परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं ने जो संकल्प पेश किया है, उसके बारे में मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए संरक्षण के सम्बन्ध में संविधान में जो दस साल की अवधि रखी गई है, उसके समाप्त होने की तारीख से दस साल और उस अवधि में बढ़ा दिए जायें। आज इस युग में हरिजन और आदिवासी, जिनको आगे लाने के लिए संविधान में सुविधायें दी गई हैं, आगे आने के बजाय पीछे हट रहे हैं। इसका कारण यह है कि शिक्षा और आर्थिक स्थिति में उनको जितना आगे बढ़ना चाहिए था, उतना वे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस स्थिति में इस संरक्षण के हटने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में हरिजनों और आदिवासियों की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है। यह देखने में आता है कि देश में आज तक छुआछूत की बीमारी मिट नहीं पाई है और गांवों में ही नहीं, बड़े-बड़े शहरों में वह मौजूद है। खासकर सरकारी कर्मचारियों में भी यह छुआछूत नहीं मिटी है।

जो हरिजन कर्मचारी सरकारी नौकरियों में हैं उनको भी हीन दृष्टि से देखा जाता है और ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि उनको दूसरी जगहों पर देखा जाता है। यह कहा जाता है कि ये हरिजन हैं, ये अमुक जाति के हैं और इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और किया जाता है। हरिजन तथा आदिवासी जो इस देश में रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है, वे बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और उनको दूसरे लोगों के बराबर लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन इस में समय लगेगा, इसमें काफी देर है। आज अगर हमको जो संरक्षण मिले हुए हैं, वे यदि खत्म कर दिए जाते हैं तो हम इस बात की कभी भी आशा नहीं कर सकते हैं कि हम इस देश में कभी आगे भी आ सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पिछड़ी हुई कौमें हैं। काफी संख्या में ये लोग गांवों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उनको जमीन नहीं दी जाती है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए अन्न नही हैं। उनको पहाड़ों से लाकर मैदानों में बसाने का जो प्रश्न है वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। हरिजनों को बसाने के लिए राज्य सरकारों ने जो कोटा एलाट किया है, उसके अनुसार भी इन लोगों को जमीनें नहीं दी गई हैं। ऐसी सूरत में हमें जो संरक्षण प्राप्त हैं यदि वे खत्म हो गए तो मेरा पक्का विश्वास है कि हम लोग दूसरे लोगों के बराबर नहीं आ सकेंगे।

मैं आपके सामने शिक्षा की बात को ही लेता हूं। केन्द्रीय सरकार से जो छात्र-वृत्तियां विद्यार्थियों को मिलती हैं, जो सहायता उनको मिलती है, वह रेगुलरली उन लोगों को राज्य सरकारों की ओर से नहीं मिल पाती हैं और जो लोग पढ़ लिख भी किसी तरह से पाते हैं, उनको भी समय पर नौकरियों में नहीं लिया जाता है, जो नौकरिया उनके लिए रिजर्व कर रखी हैं, वे उनको नहीं दी जाती हैं। इस तरह से जो कार्य आज हो रहा है, वह ठीक नहीं है। इस वास्ते यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस बारे में सोचें।

जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसमें मैंने यह सुझाव दिया है कि जो संरक्षण हमें प्राप्त हैं, उनको दस साल के लिए और बढ़ा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

> "This House is of opinion that Government should introduce legislation to amend the Constitution so that the period of reservation of seats in the Lok Sabha and the State Legislatures provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 334 is extended to a further period of ten years".

Now, may I have an idea as to how many Members wish to participate in the discussion? —I find that about 40 Members wish to speak. Hon. Members would themselves realise that even with a time-limit of 7 minutes, we cannot accommodate so many Members.

Shri Manaen (Darjeeling): May I submit that the allocation of time may be on a State basis?

Mr. Deputy-Speaker: I have no objection to that. All States should be represented. But still others would feel that they should also be allowed time. I would see that all States are represented, but then I have to make a choice. How can everybody speak? Hon. Members will appreciate my difficulty. If they can decide among themselves and form groups, that certainly would make my task easier.

Shri Yadav (Barabanki): Parties should also be taken into consideration.

Mr. Deputy-Speaker: Parties also would be taken into consideration.

There are two amendments tabled.

Shri B. K. Gaikwad: I want to move amendment No. 1.

Mr. Deputy-Speaker: That is out of order.

Shri Vajpayee (Balrampur): I beg to move:

> "That in the Resolution,—*for* the words 'ten years' the words 'five years only' be *substituted*".

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House. Shri Kodiyan. The time-limit is 7 minutes.

Shri Kodiyan (Quilon—Reserved—Sch. Castes): The question before the House is whether the period of the right of reservation conferred upon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 334 of the Constitution should be extended or not. To answer this qustion, we have to examine the circumstances that led to the inclusion of this particular article in the Constitution, and see whether the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the time of the framing of the Constitution have now changed for the better so as to do away with this special right of reservation of seats for them in the State legislatures and in Parliament.

When we go into the question as to what has taken place during the last six or seven years, we can see that certainly a considerable amount has

[Shri Kodiyan]

been spent for the upliftment of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But the real question is whether this ameliorative work in various welfare schemes has enabled the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to stand on their own legs as equals to other citizens of the country. One need not argue much to show that the conditions have not improved much. The Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is an eloquent testimony to show how far the conditions have improved. They are still very backward and very deplorable. The progress made so far in this connection has not been one which everybody expected when various measures were introduced.

At the time this particular article, 334, was discussed in the Constituent Assembly in 1949, several Members felt that the time limit fixed for the reservation of seats in Parliament and in the State legislatures was not enough. Some of them even moved amendments. But ultimately the Constituent Assembly decided the time limit to be 10 years. If we examine the objective conditions and realities of life today in our country, we can find that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not come to the level of other citizens of the country. If this reservation is to be withdrawn, they cannot get themselves elected to the various legislatures as well as to Parliament.

Take, for example, the case of various Upper Houses in the States and also the Rajya Sabha here where elections are taking place now—as ordinarily in the case of the Legislative Assemblies and the Lok Sabha—where there is no reservation of seats. The representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Rajya Sabha and also in the Upper Houses in States is hardly one per cent.—perhaps in the Rajya Sabha it may come to three per cent. Therefore, I am strongly in favour of extending the period of reservation by a further 10 or 15 years. I do not think that within those 10 or 15 years, everything will be set right and these people can stand on their own legs and contest elections freely to send their representatives to the various legislatures.

Therefore, I request Government to consider very seriously the extension of the time-limit of this reservation and accept the Resolution.

श्री बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ पेश है, उसमें मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है। इस संशोधन से यह स्पष्ट है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो सीटें रिजर्व करने की बात है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन वह रिजर्वेशन कितने समय के लिए होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा मतभेद है।

जब संविधान परिषद ने इस प्रकार की व्यवस्था हमारे विधान में की थी, तब उन लोगों के दिमागों में यह बात बिल्कुल साफ थी कि यह एक टैम्पोरेरी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है और शीघ्र ही वह समय आना चाहिए जब हमारे शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बंधु जनरल सीट्स से भी चुनाव जीत कर राज्यों की विधान सभाओं और संसद् में जा सकें। हम देखते हैं कि इस दिशा में थोड़ी सी प्रगति हुई भी है। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो रिपोर्ट कमिशनर महोदय ने पेश की है उसके अनुसार लोक सभा में छः सदस्य ऐसे हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से आते हैं, किन्तु जो जनरल सीटों से चुने गए हैं। यह एक बड़ा अच्छा लक्षण है और उसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए।

मैं यह मानता हूं जो भी चुनकर आए हैं, उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो दिशा है, वह दिशा सही है और अन्ततोगत्वा, आखिर में, हमको उसी दिशा में जाना है। जो भी रिजर्वेशन किया गया है, वह सदैव के लिए कायम नहीं रह सकता है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होगा, अस्पृश्यता का अन्त होता जाएगा। यह परिवर्तन हो भी रहा है और अस्पृश्यता भी मिट रही है। जैसे-जैसे देश में आर्थिक निर्माण होगा, विषमता दूर होगी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसमें यह भेद करना मुश्किल होगा कि कौन सा शैड्यूल्ड कास्ट का है और कौन सा शैड्यूल्ड, ट्राइब का है और कौन सा उनमें से नहीं है। हमने जैसे सामाजिक निर्माण का चित्र अपने सामने रखा है, उसमें ऐसी अवस्था जल्दी आनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक मतभेद की बात पैदा होती है। कभी-कभी उस सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को उसी तरह से बनाये रखने की कोशिश की जाती है और वह इसलिए कि जो सुविधायें मिलती हैं, वे कायम रहें। मैं समझता हूं यह प्रवृत्ति जो धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही है, यह ठीक नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जिस बुराई को समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम ऐसे उपाय अपनाते हैं कि जिन से वह बुराई बढ़ती जाती है। एक खतरा है और वह यह कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी पृथकता की भावना को अधिक न बढ़ाये और इस तरह के संकेत किए गए हैं कि एक वैस्टिड इंटिरेस्ट डिवेलेप होता जाता है और जिन्हें पूरी तरह से हम मिलाने का प्रयत्न करते हैं, वे थोड़ा सा अलग ही रहना चाहते हैं। इस पृथकता को कभी कभी राजनीतिक हथियार बनाया जाता है और उसके द्वारा राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रवृत्ति न तो जिन के नाम पर वह की जाती है, उनके ही हित में है और न राष्ट्र के ही हित में है और उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है।

हमारे सामने जो ध्येय है वह बिल्कुल स्पष्ट है। वह यह है कि हम अस्पृश्यता और आर्थिक पिछड़ेपन का उन्मूलन करना चाहते हैं और इस दिशा में जो भी काम हुआ है, मैं उसे पर्याप्त नहीं कहता। मगर हम आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम सब एक रूप हो जायें, एक रस हो जायें और कोई पिछड़ा हुआ न रहे, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे देश में देखने को न मिले। इसी दृष्टि से मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है कि रिजर्वेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, किन्तु केवल पांच वर्ष के लिए और इन पांच वर्षों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हम इस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन करें, जिनके द्वारा हमारे जो बंधु पिछड़े हुए हैं वे दूसरे लोगों के समान स्तर पर आ जायें। सामाजिक कार्यक्रमों से या आर्थिक कार्यक्रमों से उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, अवश्य ही बराबर के स्तर पर लाया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें कुछ अधिक सुविधायें भी दी जानी चाहिएं, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। मगर उन सुविधाओं को शाश्वत बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। जो भी सुविधायें दी गई हैं, वे स्थायी नहीं हैं और शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसा समय लाना चाहिए जिसमें कि इस प्रकार का पिछड़ापन दूर हो सके, इस बात की आवश्यकता है। इस समस्या को हमें इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण को अगर हम अपनायेंगे तो परिवर्तन की जो गति धीमी है उसको तेज किया

जा सकता है और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हैं उसको भी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है।]

श्री आंगडे (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व सदस्यों ने जो भाषण दिये मैं समझता हूं कि वे इस बात से सहमत हैं कि हरिजन और आदिवासियों को जो संरक्षण प्राप्त हैं वह ५ वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाय, उनमें और हमारे में भेद केवल इस समय को लेकर है। हम यह संरक्षण १० वर्ष के लिए चाहते हैं जब कि वे माननीय सदस्य केवल ५ वर्ष के लिए ही चाहते हैं। उनका यह कहना गलत है कि हम एक विशिष्ट वर्ग या एक वेस्टेड इंटरेस्ट को परपिचुएट करना चाहते हैं या उसको क़ायम रखना चाहते हैं। हमने शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के रिजरवेशन के लिए १० वर्ष की अवधि का एक्सटेंशन मांगा है। हजारों साल की जो रूढ़ि और परम्परा है वह कोई ऐटम बम या स्पूतनिक नहीं कि फ़ौरन हो जाय और इस भौतिक जगत में परिवर्तन लाने में ५० वर्ष से भी ज्यादा समय लगा है और जिस मानसिक जगत में देहातियों के दिमाग बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं, उनको हम केवल ५ वर्षों के अन्दर उस जकड़न से दूर कर सकेंगे यह सम्भावना के विरुद्ध है और यह हमारी सम्भावना के बाहर है और इसलिए हमने यह मांग की है कि उनके रिजरवेशन का पीरियड १० साल के लिए और बढ़ा दिया जाय। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने जो यह कहा कि हमारे हरिजन और आदिवासियों में अलगत्व की भावना पैदा न हो और सेप्रेट टेंडेंसी पैदा न हो जाय। मैं नहीं समझता कि इससे हमारे अछूत जाति के भाइयों में कैसे अलगत्व की भावना पैदा हो सकती है। उन अल्पसंख्यकों के बारे में तो अलबत्ता यह चीज समझ में आ सकती है क्योंकि वे कभी न कभी इस देश में और दूसरे देशों में सैकड़ों वर्ष तक शासक रहे हैं और इस कारण वे अपनी आर्थिक अवस्था और शैक्षणिक अवस्था में काफ़ी परिवर्तन कर चुके हैं, उनकी बुनियाद जम चुकी है और इसलिए उनका रिजरवेशन रहे या न रहे, उनके लिए कोई अनुचित बात नहीं है लेकिन इस देश के जो हमारे आदिवासी और अछूत भाई हैं वे आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों में से आर्थिक और राजनैतिक गुलामी का जीवन बिताते आ रहे हैं और उनमें यह अलगत्व की भावना कैसे आ सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों में अलगत्व की भावना है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हमने अपनाई हुई है और उसमें सवर्णों और दूसरे आम लोगों ने ६ हरिजनों और आदिवासियों को जनरल सीट्स पर चुना है। हम ने अलगत्व की भावना पैदा नहीं की। आपने ही उनको चुना है। इसलिए आपका यह कहना और माननीय सदस्य का यह आशय कि इससे अलगत्व की भावना पैदा होती है, स्वयं उनके मुंह से ही कट जाता है।

सरकारी विभागों को छोड़ कर आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज में देखिये कि क्या अवस्था है। जितने भी प्राइवेट उद्योग धंधे जिन पर कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है जहां पर सरकार का आधिपत्य नहीं है उनमें आदिवासियों और हरिजनों को कितने स्थान मिले हुए हैं और उनको क्या सुविधाएं वहां पर प्राप्त हैं। बड़े बड़े शहरों, देहातों और कस्बों में जहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर व्यवसाय चलते हैं अथवा प्राइवेट लोग चलाते हैं, उन उद्योगों में लगे हुए हरिजन और आदिवासी लोगों की हालत बड़ी शोचनीय है, स्लम्स में वे लोग रहते हैं, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बाहरी शत्रुओं से और

हमारे शोषण से पीड़ित हैं और मैदानी इलाक़ों में रहने वाले भाई भीतरी कलंक और कलह से पीड़ित हैं। ऐसी हालत में अगर हम हरिजनों और आदिवासियों के लिए इस रिजरवेशन की मियाद को १० वर्ष के लिए और बढ़वाना चाहते हैं तो क्या गलत करते हैं। आज के जमाने में हम देखते हैं कि हमारा जीवन राजनीति से बहुत प्रभावित होता है और पार्लियामेंट और अन्य प्रान्तीय धारा-सभाओं में जो जोरों से बोल सकता है और अपनी मांग के लिए अच्छी वकालत कर सकता है, उसकी सुनवाई होती है और वह फ़ायदे में रहता है। मैं मानता हूं कि हमारे सवर्ण हिन्दू भाइयों में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि हमारा हित चाहते हैं और उसके कारण आज देश में अनुकूल वातावरण पैदा हो रहा है फिर भी आप समझ सकते हैं कि दूसरे सवर्ण हिन्दुओं के बराबर आने में हरिजनों को अभी बहुत कम समय लगेगा। हमारे हरिजन और आदिवासी भाइयों के पैर आर्थिक और राजनैतिक गुलामी की जंजीर में सैकड़ों और हजारों वर्षों से जकड़े हुए हैं और आप उनसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एक दम से वे घुड़दौड़ में अन्य अन्य सवर्ण जातियों के बराबर दौड़ सकेंगे? एक घोड़ा जो कि अस्तबल में हमेशा बंधा रहता है, पैर उसके जकड़े रहते हैं और उसके खाने पीने का कोई ठीक इंतजाम नहीं होता वह एक मस्त घोड़े के बराबर जिसको कि पूरी आजादी है और जिसको कि सब चीजों का आराम है उसके बराबर रेस में कैसे दौड़ सकता है और यक़ीनी बात है कि वह उस मस्त घोड़े से पिछड़ जायेगा। ठीक यही हालत हमारे हरिजन भाइयों की है। वे आज से नहीं अपितु सैकड़ों और हजारों वर्षों से पीड़ित अवस्था में रहते आये हैं और उनका हर प्रकार से शोषण होता आया है, आज एक दम से उनसे आप यह कैसे उम्मीद करते हैं कि वे अन्य सवर्णों की बराबरी कर सकेंगे। वह घोड़ा जो कि टी० बी० आदि रोगों से ग्रस्त हो वह उस मस्त घोड़े की रेस में कैसे बराबरी कर सकता है जो कि आराम से हजारों सालों से दाना खाते खाते मस्त हो गया है? इसलिए अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजरवेशन की मियाद १० वर्ष के लिए और बढ़ाये जाने की मांग की जाती है तो वह कोई बेजा बात नहीं करते हैं।

अभी आप देखिये कि हमने कई स्थानों में उनको संरक्षण नहीं दिया है। राज्य सभा, नगरपालिकाओं, निगमों, ग्राम पंचायतों और विधान परिषदों में हमने हरिजनों को संरक्षण नहीं दिया है, वहां पर उनकी संख्या कितनी है? आज हम देखते हैं कि सैकड़ों वर्षों से सरकारी नौकरियों में हरिजन और आदिवासियों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उनका कोटा पूरा नहीं होता है और उनकी जगह होते हुए भी हरिजनों को नहीं रक्खा जाता है और बार बार शासन की ओर से यह कह दिया जाता है कि हरिजनों और आदिवासियों में एफ़िशियेंसी न होने के कारण और योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण वह जगह खाली कर दी गई और वह स्थान दूसरों के द्वारा भर दिया गया। दूर क्यों जाइये इसी संसद् में और दूसरी विधान परिषदों में जहां कि हरिजन और आदिवासी लोग चुन कर आये हैं, आप देखिये कि वे कितने पढ़े हैं, उनकी क्या योग्यता है, मैं कटाक्ष नहीं करता लेकिन उसको कोई भी देख सकता है।

आखिर हम जो संरक्षण मांग रहे हैं वह किसी दूसरे के अधिकार को छीन कर तो नहीं मांग रहे हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासियों और हरिजनों की जितनी संख्या है उसके अनुपात से हमें जगहें दी जायें। हम तो यह मांग कर रहे हैं कि हमारी संख्या के अनुपात से हमें रिजरवेशन दिया जाय और यह मांग करके हम किसी दूसरे के अधिकार को नहीं छीन रहे हैं। और फिर हम लोग जो

कि हमेशा से दूसरों के आश्रित रहे हैं और उनके नीचे रहते आये हैं, कैसे हम २ वर्ष के भीतर उनके बराबर आ सकते हैं। पिछले आठ वर्षों में हमारे लिए किये गये प्रयत्नों का जिक्र शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में मिलता है और उसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में संसद् और विधान परिषदों में दिये गये उत्तरों से पता चलता है कि हमारे उद्धार के लिए किये गये प्रयासों की गति बहुत ही धीमी रही है और उस हालत में क्या २ वर्षों क अ ?? जितनी तरक्की हम चाहते हैं कर सकेंगे ? मैं समझता हूं कि हम नहीं कर सकेंगे और इसलिए हम मांग करते हैं कि इस रिज़र्वेशन की अवधि को १० साल के लिए और बढ़ा दिया जाय और अगर ऐसा किया जाता है तो वह कोई बेजा चीज नहीं होगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ७ मिनट से ज्यादा समय लेने का यत्न नहीं करना चाहिए।

Shri B. K. Gaikwad: Mr. Deputy-Speaker, Sir, of course I have no time at my disposal and so I will be very brief.

I know that the position of the Scheduled Caste people in this country was worse, and even today, it is worse. That much I admit. The question now before us and the country is how that can be improved.

I would bring to the notice of this hon. House that in the very beginning no representation was given to the Scheduled Caste people. They were sent by nomination to the Legislatures, the local boards and so on. But, when persons from India were called to England as members of the Round Table Conference, at that time when the question was discussed, it was Dr. Ambedkar who fought and fought and got the reservation, this representation for the Scheduled Caste people. But, it is a long long history and I do not want to repeat it. He demanded that the Scheduled Caste people should get due representation and, accordingly, the Communal Award was given by the late Prime Minister for England, Ramsay MacDonlad. Due to communal Award, there was separate electorate given. As soon as it was heard by Mahatma Gandhi, he started a big fast. He went on fast in Yerrawada prison.

Of course, I do not want to repeat the whole history. There was the Poona Pact. In the Poona Pact, joint electorate was accepted. The late Dr. Baba Saheb Ambedkar was opposing this because we were fighting to safeguard the interests of the downtrodden Scheduled Caste people. Against whom are we going to safeguard our interests? We are not going to safeguard our interests from the Britishers or from the Muslims who had gone to Pakistan or from anybody else. We are going to safeguard our interests from the caste Hindus whom we call our brothers...

An Hon. Member: There was no Pakistan then.

Shri B. K. Gaikwad: We want to safeguard our interests from the Caste Hindus of this country. And, now, what does the joint electorate say? It says that we will be elected with the help of the Caste Hindu votes and Scheduled Caste votes. You will find that a well known leader and drafter of the Constitution, one who faught for the cause of the Scheduled Castes and who was a real representative of the Scheduled Castes, tried his level best and contested two or three elections but was defeated. Why?

Pandit K. C. Sharma (Hapur): And Churchill was defeated in England.

Shri B. K. Gaikward: He was dfeated only because he was fighting the right cause of the Scheduled Caste people. That was why the

Caste Hindus would not vote in his favour. That is well known. I do not want to ... (*Interruptions*)

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has got only 7 minutes and he should not be disturbed.

Shri B. K. Gaikwad: So, these are the things. The question before us is this. There are reservations. But, always we have to express our views according to the views of our voters. Our voters are, in a large majority, Caste Hindus. We are not in a position to represent our real cause, the cause of Scheduled Castes. In this House there are about 80 representatives of the Schedueld Castes. Do you mean to say that they have no grievances, no disabilities? Supposing we put our grievances before the House, naturally, next time people will not elect us. That is the fear in the mind of all the people.

I just want to say at this stage very frankly one thing and it is this. The Scheduled Castes Federation, of which the late Dr. Baba Saheb Ambedkar was the President, is a party of the Scheduled Castes alone and none else. You will find no other party in India representing the Scheduled Castes. I know there are representative who are from Congress and from other parties. But, to fight the cause of the Scheduled Castes only, there was only one party and that was the Scheduled Castes Federation of which Dr. Ambedkar was the President. As President of the Federation he passed a resolution. I will just read it out. It was passed in a meeting of the working committee held at Bombay on the 21st August, 1955, under the chairmanship of Dr. Ambedkar. It said:

> "This meeting of the Working Committee is of opinion that the provision for the reservation of seats for the Scheduled Castes in the Parliament, in the State Assemblies, in Municipalities and District and Local Boards be done away with immediately, even before the next elections."

That was the resolution passed by the Scheduled Castes Federation. I say that the late Dr. Baba Saheb Ambedkar and his party are the only representatives of Scheduled Castes in India: We passed this resolution and expressed our view as to what we think about these things. That is because no real representatives are elected. There is a proverb in Marathi which says:—

> *Milimit sawa bhagya pesha dhal dhalit vaidyavya bare.*

The meanning of this proverb is, it is better to be a widow than to become the wife of an important person.

I will say that it was the position here. We are now prepared to stand on our own legs and fight for all these things instead of running behind other organisations. It is nothing but political slavery. As soon as you take away the reservations, all our friends, whether in the Congress or other parties, will understand their responsibilities and will join hands together and realise what things they have to do. As long as reservations are there, every party is after them, and because the Scheduled Caste Federation was of Scheduled Caste people and none else, we were defeated. As the hon. friend who preceded me has said, our population is so much. We are not demanding more. We are demanding on the population basis. I do agree. But this community is divided in so many other groups only because every Party is after we people. Without doing anything, they think they get this representation. When the impression is corrected, we will all be united for a common cause and we will get what is our due share. With these words, I oppose this Resolution.

Shri M. R. Krishna (Karimnagar—Reserved—Sch. Castes): Sir, before

[Shri M. R. Krishna]

I commence my speech, I would like to make a request. Just as we appeal to the Government through the Resolution to extend the reservation, I would like you to extend the time for my speech.

Mr. Deputy-Speaker: It would not be possible because the Members of the Scheduled Castes have decided on that and so I cannot change it.

Shri M. R. Krishna: Sir, I stood up to speak not in the interest of the Scheduled Castes. I am speaking in the interest of the caste Hindus and in the interest of the other non-Scheduled Castes in the country. When I say this, I think it is not necessary for me to elaborate my speech in the seven minutes' time. But the speech which has been delivered by my friend, Shri Gaekwad, will clearly prove what the different political parties are aiming at while they are agitating for the withdrawal of this concession given to the Scheduled Castes. If you want me to narrate the whole story as to how this reservation came into being, there was the communal award which has been described and then the Poona Pact. Everything flowed from that. Well and good.

My friend Shri Kodiyan has described that in places like the Rajya Sabha or the upper houses in the State legislatures, there is no reservation. We find that there is not even one per cent representation of the Scheduled Castes. If the reservation is withdrawn, I think that only six persons who are elected to this House on a separate issue would be there and they came from Bombay on the Samyuktha Maharashtra issue . . . (*Interruptions.*)

Some Hon. Members: No, No.

Shri Tangamani: What about Mr. Kodiyan?

Shri Vajpayee: What about Shri Sivaraj?

Shri M. R. Krishna: Only six persons will be decorating this House as representatives of the Scheduled Castes and not the other eighty Members who are representing the Scheduled Castes of the country who would not be here but for the reservation. I think I have made it quite clear.

The Scheduled Castes Commissioner brings out a report giving the progress that has been made in the country by the various State Governments. That should give an indication to the Government to either continue the reservation or withdraw it. The other day, the Home Minister said in the other House, that in 1962, the Government would consider whether the extension should be granted or not. Today the Home Minister is replacing the great leaders like the Father of the Nation and Thakkar Baba. We the Scheduled Castes have great faith in him. We trust what he says. He will definitely do that.

My simple question is this. In the condition in which the Scheduled Castes are today, does the Government feel that they have reached that stage where it would like to dispence with the reservation in 1962. It is not a long way of. Are we going to do everything that we have not done all these eleven years in the coming four years? I doubt very much.

When the framers of the Constitution fixed this ten years' time, they had a certain speed in their minds. They thought that within ten years in the independent India, people would realise their responsibility and would know how to treat their brethren. So, they thought that in ten years' time this social advancement in education, economy and other things which Gandhiji had been preaching would be achieved. So, they felt that this reservation could be dispensed with in ten years' time. But at the same time, the Chairman of the Drafting Committee has said

one word. He has quoted perhaps Abraham Lincoln. "Small minds and big empires go ill togeher."

Shri C. K. Bhattacharya (West Dinajpur): It was Edmund Burke.

Shri M. R. Krishna: Somebody said it; I am not concerned with who said it.

Mr. Deputy-Speaker: Whoever it is, it is Shri M. R. Krishna now and he should be content to hear.

Shri M. R. Krishna: Even the framers of our Constitution were not certain that within ten years, they would be able to root out all the evils. The Scheduled Castes have been suffering from ages. If people like Vivekananda, Ramakrishan Paramahansa and Gandhiji could not do it, if anybody thinks that it could be done in ten years' time or that all the disabilities that these people are suffering from could be eradicated within ten years, it is something which we cannot certainly believe.

I can understand if within these three or four years the Government brings up another plan and says that it is going to advance these people or that certain schemes are being drafted for the welfare of the Scheduled Caste people and that these are the means that it is going to employ and if the House is convinced about it. We will be able to understand that there is some truth in what is said and that some interest is being shown to their welfare. But in the absence of such a thing, we cannot simply think that in 1962 all the problems that are being faced by the Scheduled Castes will be solved.

There are a lot of things which I will have to bring to the notice of this House. What could have been done in the field of education for these people in ten years? A boy could have gone to the matriculation standard from the primary class. Beyond this, I do not think that big engineers or scientists are produced. Every day we put questions and no department could convince this House by saying that they have reached a 12·5 per cent quota. At this rate, I do not think that we will be able to reach the target even after these ten years.

If at all any concession is shown or given to the Scheduled Castes, I want the Government to extend those concessions honourably. It should not be made to appear that the Scheduled Castes are just beggars or that somebody is going to give them something for begging. Everything that is to be given to them should be honourably given to them. Not only in this House, but even in the country, they have been suffering for ages. Muslims have been having reservation for sixty years. The Christians have been enjoying reservation right from 1935. The Scheduled Castes had only ten years and within these ten years we could not benefit the First and Second Plans properly and the results of the First and Second Plans will be derived only in the Third Plan. The Government should be considerate enough to give them some of these benefits. So, I fully support this Resolution and I hope the Government will definitely accept it.

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा-रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर तो तीन भाषण हुए और एक ऐसा भी भाषण हुआ जिसमें रिजरवेशन का विरोध किया गया, रिजरवेशन की जो मांग की जा रही है उसका विरोध किया गया। आप देखें कि यह रिजरवेशन का विरोध ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा हो रहा है जो कि चुनावों में हार जाने के कारण फ्रस्टेट हुए हैं। इसका विरोध करने वाले ऐसे ही लोग हैं जो या तो हार गये हैं या जिनके दिल में यह बात नहीं है कि हरिजन समाज के अन्य लोगों के समान ऊंचे हो जायें।

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

आप जानते हैं कि जिस समय कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में रिजरवेशन देने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो उस वक्त सब सदस्यों की यही राय थी कि यह जो दस वर्ष का समय है वह अधूरा है। इतना ही नहीं परन्तु बाबा अम्बेडकर ने, जिनके अनुयायी आज इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कांस्टीट्यूशन असेम्बली में जो कहा था उसका उद्धरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। उन्होंने कहा था :

"I personally was prepared to press for a larger time, because I do feel that so far as the Scheduled Castes are concerned, they are not treated on the same footing as the other minorities."

Shri B. K. Gaikwad: Read the Resolution which was passed under his presidentship in the year 1955; that is the recent one.

श्री बालकृष्ण वासनिक : मैं आज यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि डाक्टर साहब ने अपने भाषण में आगे यह कहा था :

"If at the end of ten years, the Scheduled Castes find that their position has not improved or that they want further extension of this period, it will not be beyond their capacity or their intelligence to invent new ways of getting the same protection which they are promised here."

डाक्टर साहब ने जो अदर वेज के बारे में कहा उसके सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम तो वैधानिक तरीकों से ही इस पीरियड को बढ़वाना चाहते हैं। २८ फरवरी १९५७ को इसी प्रकार का एक प्रस्ताव राज्य सभा में आया था और उस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए पंडित पन्त होम मिनिस्टर ने, आप जानते हैं, यह मान्य किया था कि आज हरिजनों की हालत कुछ इतनी सुधरी हुई नहीं है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो कर दूसरे समाज के साथ बराबरी से काम करने लगें। उनका एक वाक्य मैं यहां पर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

"I recognise, however, that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not today in a position to stand on their own legs and to occupy such a position as would enable them to hold their own against other sections of the community."

परन्तु इतना मान्य करने के बावजूद भी होम मिनिस्टर साहब ने आगे कहा कि यह जो सवाल है यह सवाल फिलहाल न तो अरजेंट है और न इंपारटेंट है। उनके कहने का मतलब इतना ही था कि धारा संविधान की ३३४ का जो प्रोवीजो है उसमें यह कहा गया है कि यह जो प्रेजेंट हाउस है यह जितने दिनों तक रहेगा उतने दिनों का यह रिजरवेशन रहेगा। परन्तु आप जानते हैं कि यह प्रोवाइजो किस स्थिति में हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में श्री नाजिमुद्दीन ने इस प्रोवीजो को मूव किया था और उसको मूव करते वक्त उन्होंने कहा था :

"The point is that the expiration of ten years from the commencement of the Constitution and the expiration of the Life of the House of the People or of the States Assemblies may not coincide. It may be that for various reasons the second election is held in the ninth year of the passing of the Constitution. Then there would remain only one year for the completion of ten years but there would be an unexpired period of four years for the Legislature to expire. What is ambiguous is that,

on the expiration of ten years the duration of the Assemblies might not have expired."

इस प्रकार से यह केवल दस वर्षों का समय निर्धारित करने के बाद में एक विचित्र सी परिस्थिति निर्माण हुई होती कि ये जो रिजर्व्ड जगहों पर चुन कर आए हुए सदस्य हैं, यदि दस वर्ष समाप्त हो जाने के बाद फिर हाउस रहता है, तो उनकी सीटों का क्या हाल होगा ? क्या वे फिर कान्टीन्यू करेंगे या रिजर्वेशन खत्म हो जाने के बाद उनकी सीटें चली जायेंगी और फिर दूसरे चुनाव करने पड़ेंगे ? ऐसी कोई विचित्र परिस्थिति निर्माण न हो, इसलिए वह प्राविजन किया गया था और मेरा ख्याल है कि केवल उस प्राविजन का सहारा लेकर यदि आज हम इस बात को कहने लगें कि हम दो तीन साल और ठहर जायें और फिर बाद में इस कांस्टीट्यूशन को अमेंड करने का सवाल उठाया जाय, तो यह उचित होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है । वास्तव में इन्हीं दस वर्षों में यह रिजर्वेशन समाप्त हो रही है । आप जानते हैं कि आज अस्पृश्यों और हरिजनों की हालत कुछ सुधरी हुई नहीं है । उनको कुछ और समय तक रिजर्वेशन, संरक्षण देने की अत्यन्त जरूरत है । इन सब दृष्टियों से यदि आप देखेंगे, तो आप पायेंगे कि रिजर्वेशन का पीरियड बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है ।

एक और बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । आज हरिजनों में कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं, जो उन में द्विराष्ट्रवाद की भावना निर्माण करना चाहते हैं, जो उन को सामान्य सवर्ण हिन्दु समाज से तोड़ कर, अलग कर के इन दोनों समाजों में द्वेष और विद्वेष की भावना को पनपा कर अपनी नेतागीरी बनाना चाहते हैं । मैं आपसे कहूंगा कि वे लोग जो अस्पृश्यों में द्विराष्ट्रवाद की भावना का निर्माण करना चाहते हैं, जो अस्पृश्यों और सामान्य सवर्ण हिन्दुओं में द्वेष की भावना को पनपाना चाहते हैं, केवल अपनी लीडरशिप को बनाने के लिए, केवल असेम्बली में कुछ स्थान और ऐसी दूसरी चीजों को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं । उन लोगों से अस्पृश्यों का संरक्षण करने के लिए और समाज को विद्वेष की भावना से बचाने के लिए यह रिजर्वेशन का पीरियड कुछ समय के लिए बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

Shri B. C. Mullick (Kendrapara—Reserved—Sch. Castes): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to offer my whole-hearted support to the resolution moved by my hon. colleague Shri Deen Bandhu Parmar. There are several reasons for my supporting the resolution.

When article 334 was passed by the framers of the Constitution of India it was supposed that by having this reservation Government would be able to mitigate the series of miseries from which the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have suffered for centuries. It was also the purpose of that article to bring them to a position where they can stand on their own legs, and also to remove handicaps such as educational, economic, social and political from which they were suffering.

But, may I ask the Government whether they can say that they have brought these poor people to such a position? The answer will certainly be in the negative. In this connection I would like to refer to the speech delivered by Pandit G. B. Pant in Rajya Sabha where he said:

"I recognise, however, that the Scheduled Castes are today not in a position to stand on their own legs and to occupy such a position as would enable them to hold their own against other sections of the community."

[Shri B. C. Mullick]

He also said:

> "Similarly, the Scheduled Tribes also hold a very weak position."

Therefore, it is clear that the purpose of article 334 has not been fulfilled. That is one of the reasons why I support this resolution.

The Government have spent Rs. 39 crores in the First Five Year Plan and a sum of Rs. 91 crores has been allotted in the Second Five Year Plan for the uplift of Harijans and Adivasis. Even though two years of the Second Plan have elapsed, where is the progress? It is found from the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that the progress achieved in this direction is very poor. This is due to lack of co-ordination among the various departments, especially the State Governments do not take much interest to implement the suggestions. It shows that they have not fulfilled the purpose guaranteed by the Constitution.

It will be a great injustice to these 8 crores of people who are still downtrodden, suppressed, oppressed and depressed in every corner of India, if you take away the reservation after the dissolution of the existing House. In Rajya Sabha, Sir, as there is no reservation there is no representative of the Scheduled Castes from the Orissa State in that House. That is why I stress the need for providing reservation in the Upper House and the Legislative Councils.

As far as the services are concerned, it is said that due to non-availbility of suitable candidates from Scheduled Castes and Scheduled Tribes the reserved quota is not filled up. This is one of the aspects where the Constitutional guarantee has not fulfilled its purpose. Moreover, as a representative of the Scheduled Castes, I request the Government to implement the guarantees gives in the Constitution.

Some Members in the Rajya Sabha, in the course of the discussion, said that instead of reservation, there may be nomination. But this will create a great trouble. The nominated person will not see to the real grievances of the people of this community. One's responsibility to one's constituency will not be there, and evils such as nepotism, corruption, etc. will persist. So, the extension by ten years will not lead to any separatism. It would rather pave the way to provide political education to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They will then be able to stand on their own legs and not depend on others.

The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has said as follows at page 10 of the report for 1956-57,—6th Report:

> "In some quarters, it is felt that this reservation may result in the maintaining of and even perpetuating the existing distinctions on the basis of caste. This is not true. This gainful discrimination is to be tolerated so that equality may ultimately thrive."

So, the demand for an extension of the prescribed period is a legitimate demand. Recently, it was demanded in the Conference of State Ministers also, which was held in the Central Hall of Parliament House. Everywhere, such a demand has been made. This demand was emphasised at the conference of Depressed Class held at Gwalior.

Therefore, it is up to the Government to see their way to extend the period up to the two Plan periods.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Ayyakannu.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: I am calling one Member from each State.

Shri Ayyakannu (Nagapattinam—Reserved—Sch. Castes): Mr. Deputy-

Speaker, Sir, I feel it a painful duty to support this resolution at a time when our nation really wants to do away with casteism which is a fatal disease that saps the vitality of our nation. Of course, we know that casteism is a symbole of ignorance, feelings of heard, malice, errors and superstitions, and all that. It is a veritable symbol of all these things. Yet, if anybody wants to perpetuate this caste system, whether in the name of politics or in some other form, he does a disgraceful thing.

However, we should not be afraid of saying what we feel about it. It is all right to say this: for a leper to say that he is suffering from leprosy is not a sin, but, if the leper dies that is neither good for the country, society or the individual concerned. So also, so long as this monstrous disease exists in our country, we should expect that the big section should give use some protection so as to see that the other sections come up.

Coming to the real point, our Constitution permits ten years as the prescribed period for the reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is hoped that within that period, this community can come up. But I should like to pose this question to the House: how far this community has come up at the present time. In the economic field, particularly, their progress is zero. Nothing has been done. They have not given any protection so far as the economic field is concerned.

More important than this,—It is painful for me to say it—there is not even a single transport permit-holder in this country from the Scheduled Castes. There is not even one permit-holder in regard to export and import from this community. It is not because these people are incapable of undertaking such tasks. I can give the House an example, and I should be excused if I make a personal reference. The father-in-law of our revered leader, Shri Shiva Raj, a Member of this House,—Shri Madura Pillai—has been a very rich man in Burma. There are so many examples. An engineer from this community has gone out of this country, and such people are doing very good business. They are earning very good amounts and they become very rich. But unfortunately we cannot shine in this unfortunate country as businessmen.

Therefore, unless these people come on a par with others, there is no use of speaking about the abolition of this or that. Some may be under the false impression that after the abolition of this reservation, these people will rally round one banner and they will work. I say with all the emphasis at my command that it is a false notion. As long as these people are under the grip of others, you cannot expect any help from others. This subjection is not going to last.

With all humility, I should like to tell our hon. friends in the Opposition these facts. It has been said that to a certain extent, people from this community have come up in the educational line, but yet there are some difficulties. It was pointed out yesterday in this House that the UPSC is not doing justice, or any other recruiting body is not doing justice to this community. What after all, is intelligence? Intelligence is only a capacity to understand certain things. How do they acquire it? How could you expect a farmer's son to be equivalent to a son of a district judge or a son of a high court judge or a son of Minister or a son of a leader? It is totally impossible. It is a question of the circumstances.

If you are very sincere about it, let the House ask the Government to pick up the children of the Harijan community and put them in very good society; give them all facilities. I say they will certainly beat all the other communities. After all, intel-

[Shri Ayyakannu]

ligence is not the monopoly of any community.

Again, when Gandhiji was there, he was doing something about it—the removal of untouchability. After Gandhiji, there is a lull. It is painful to see that our leaders have entirely forgotton about it. After all, we do not worry whether they touch us or not, but at least they should consider us as men. Even that recognition we cannot get.

So, I appeal to my hon. friends, irrespective of party politics, to start a movement, similarly to the Bhoodan Yagna, to promote our cause, similarly movement may be started with a dynamic personality so that we can drive out this evil.

I should like to know how many of my hon. friends, even though they may work with the largest zeal in the villages, remove untouchability really? How many of my hon. friends have these untouchables as their servants in their Houses? How many of my hon. friends in this House who talk of socialism, who talk "there is no caste and other things," mingle and get married or do something like that among this community? They have done very little in that direction. Merely talking is one thing and doing is entirely different.

The time has come when something was done about it. People may say "For forms of Government, let fools contest". But that has become a theory, for the unfortunate people, because when man is really fighting for his very existence, he cannot talk about democracy. He cannot talk about individuality or liberty. So, I appeal to the Government to realise that unless some sincere steps are taken towards the improvement of the economic condition of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there will be a revolution; there will be chaos and confusion in this country.

Further, there is no use in just giving this reservation of seats and sitting quite. For example, the Commissioner for Scheduel Castes and Scheduled Tribes has given so many recommendations for every State. I take one of them for example. For instance, there should be one member of the Public Service Commission in every State, chosen from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But how many States today have got it? I do not think any State has done it. I hope the hon. Minister in the Ministry of Home Affairs will take this question seriously into consideration and see that at least some five or six States will give due representation if not all the States.

Mr. Deputy-Speaker: I will give opportunities to members from all the States

Shri Ignace Beck (Lohardaga—Reserved—Sch. Tribes): We are now considering the question of reservation of seats in the Legislatures being extended for a further period of ten years. For every question there are two sides. To this question also, there are two sides.

Now, the arguments advanced from both sides seem to me to be very plausible and valid. I would submit that this question of reservation has to be looked into from a proper perspective. I will just give one example, the instance of a child, a human being just coming into this world. There are certain people who say "throw it in the water and it will learn to swim". Is it reasonable, I ask the House. When a small baby is thrown into the water, will it swim. There is, naturally, a time for everything. A baby requires to be tended. There are certain times when the whole family, mother, father, brothers and sisters in the whole family, will look after the baby. A time comes when the child does not care or ask for any protection. Nobody cares where he has gone or where he has

been lost. After some time, he comes back safely and everyone is happy.

The position of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is also more or less similar. This resolution has been brought forward, requesting extension of protection to Members for some more time. This is just like the instance of a child. They feel that they are in such a state in the society as the child is in the family. Now, just like the child, we also require protection. Can we say: we need not take care of the child, it will take care of itself? No. We have to look after it until such time as it can look after its own affairs. We are also in the same position. We are the children of society. We must also be protected until such time as we can stand on our own legs. We are not asking for perpetual reservation or protection or anything like that.

We are trying to get out of this bondage. Just like a child cannot get away from his father, mother and brothers and sisters until he is quite grown up, similarly, we, who are the children of society, cannot be outside the care of society until we can stand on our legs. That is the object of this resolution.

It is true that there are two sides of the picture. It is said that these sections of the community need not be protected. Now, as regards the matter of time, it is provided in the Constitution that it will be ten years. It is immaterial whether it is ten or twelve years. But I do not know whether it can be solved within that period. This is a problem that has existed for centuries. For ages past it has been existing in this country. It has been there for thousands of years. So, it will take some time to counteract or come over the difficulty.

So, the matter of time does not matter very much now. If this problem can be solved in one or two, years, well and good. But if it is prolonged —it would seem that is the most probable thing—the matter of time does not matter very much. But the problem remains that in the state in which those sections of the people find themselves in the Indian society they need protection. Whether we like it or not, that protection has to be given. If the Government is serious, if the forward people are serious, I think it is not a difficult question.

I feel somewhat surprised that when the question of protection for the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes comes up, certain sections of the people seem annoyed. I would request my friends, the advanced people, to be more sincere and take the question in the correct perspective, not in the sense that we are fighting each other. That is not the question. We are not fighting against each other. We have not created that kind of feeling. We request the House to consider this question very seriously for the sake of India, for the sake of humanity, in that spirit. I would not like to say much. I think this is the fundamental thing which the House has to consider.

Shri Bahadur Singh (Ludhiana—Reserved—Sch. Castes): I will not take much time. I will give one instance only, as far as this matter is concerned. I am strongly in favour of extending the period, if not for more than ten years, at least for ten years. According to the Constitution, as we all know, reservation has been given for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament and in other local bodies.

As far as Upper Houses are concerned, Legislative Councils and the Rajya Sabha, there is no reservation. If you look into the figures, you will find that very poor representation has been given to the Scheduled Castes in the Rajya Sabha. As far as the State Legislative Councils are concerned, I shall take up only the case of the Punjab Legislative Council. The Punjab Legislative Council was creat-

[Shri Bahadur Singh]

ed in 1952. The strength of the Legislative Council was 40. There was not even a single member of the Scheduled Castes out of the 40 members. After some time the Governor had to nominate one man when he found that great injustice has been done to the Scheduled Castes. When PEPSU was merged with Punjab, the strength was raised to 53; but the number of members from the Scheduled Castes did not rise; it remained the same.

Now we can easily understand the differences between reservation and non-reservation. Those members who said that if there is no reservation, then people from the Scheduled Castes will be able to come to the State Legislatures and Parliament are very much mistaken. I would humbly ask them whether they have been elected on the reserved seats or on the general seats.

Shri B. K. Gaikwad: I have not been elected from a reserved seat.

Shri Bahadur Singh: Let those members who have been elected for the reserved seats vacate their seats and contest for the general seats and see whether they can come to the House or not.

Mr. Deputy-Speaker: There should not be any discussion between hon. Members privately.

Shri Bahadur Singh: In the latest report on Scheduled Castes and Scheduled Tribes it is stated that they have not progressed up to the mark, at least to that mark where we can think that the Scheduled Castes can stand on their own legs in all walks of life with other brethren. They are still in need of protection. Still, we cannot stand on our own legs. There is certainly a need for some persons being there for that task. That we can do only if we have got reservation.

With these two points I strongly stand for the reservation and request that, if not for more, reservation must be extended at least for ten years.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्री दीन बंधु परमार द्वारा जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्डट्राइब्स के लिए लोक-सभा और विधान मण्डलों में रिजर्वेशन की अवधि को १० वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि यह सदन भी उसका पूर्णतया समर्थन करेगा ।

मेरे एक माननीय सदस्य जो कि सामने बैठे हैं, काली टोपी वाले . . . . . .

एक माननीय सदस्य : काली नहीं नीली टोपी वाले ।

श्री नवल प्रभाकर : नीली है, ठीक है, मुझे यहां से काली नजर आ रही थी । केवल उन नीली टोपी वाले माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है । उन के अतिरिक्त सदन के सभी सदस्यों ने जो अब तक बोले हैं, उन सब ने इसका समर्थन किया है ।

जहां तक १० साल का सम्बन्ध है जो कि सन् १९५८ से लेकर सन् ६० तक का पीरियड है, उस समय के अन्दर हमें यह देखना है कि अब तक कितनी प्रगति हुई है । मैं देखता हूं कि हमारे सामने दो पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उन दोनों योजनाओं में हरिजनों के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी राशियां खर्च की गई हैं । जितनी राशि अब तक उन पर खर्च की गई है उसका यदि हम हिसाब लगा कर देखें कि सार्वजनिक रूप से प्रति व्यक्ति कितना खर्च हुआ है, उस दृष्टि से अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो पायेंगे कि हरिजन और आदिम जाति के लोगों के लिए वह राशि बहुत कम है और अगर यह काम हमें १० वर्ष में पूरा करना है तो इस राशि को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और हमें इनके कल्याण के लिए मार्ग ढूंढना है । आप विचार

कीजिये कि एक विद्यार्थी है। वह अपनी पढ़ाई आरम्भ करता है तो दस वर्ष में बहुत मुश्किल से मैट्रिक पास करता है। अब आप ख्याल कीजिये कि १९५० से जब से कि यह रिजर्वेशन शुरू हुआ है दस वर्ष में कितना कर सकता है। एक मैट्रिक पास विद्यार्थी अगर मान लीजिये पहली जमात से पढ़ना शुरू करता है, मैट्रिक पास करता है और उस वक्त वह रिजर्वेशन खत्म हो जाता है तो उसका उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर हम सब दृष्टियों से देखें तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि रिजर्वेशन की मियाद और बढ़ाई जानी चाहिए। १९६१ में जब नई जनगणना हो तो उसमें इस पर विचार किया जाना चाहिए और उसमें हिदायत और आदेश दे दिया जाना चाहिए ताकि १९५१ के आंकड़ों से मुकाबला करके हम यह पता लगा सकें कि हरिजनों की आर्थिक दृष्टि से कितनी उन्नति हुई है, पहले एग्रीकलचरिस्ट्स और नान एग्रिकलचरिस्ट्स लोग कितने थे और अब कितने हैं अब कितनों को भूमि दी गई है और कितनों के पास अब भूमि है, यह सब आंकड़े हमें इकट्ठा करना चाहिए और उसके बाद हमेंइस विषय में कोई निश्चय करना चाहिए।

जहां तक उनके सामाजिक स्तर में हुई उन्नति का सम्बन्ध है मेरा कहना यह है कि बड़े बड़े शहरों को छोड़ कर गांवों में आज भी वे उसी दलित अवस्था में रह रहे हैं और चूंकि अभी तक वांछित हृदय परिवर्तन नहीं हो पाया है इसलिए सरकार को उसके लिए पिछली बार क़ानूनी व्यवस्था करनी पड़ी।

कानून बन गया, किन्तु गांवों के अन्दर आज भी उसका कोई भय लोगों में नहीं है। मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो देखता हूं आज भी हरिजनों की सामाजिक अवस्था उसी तरह से है। मैं मानता हूं कि दिल्ली में और राज्यों की अपेक्षा कम छुआछूत बरती जाती है। यहां अस्पृश्यता कुछ कम है, किन्तु जितनी भी है वह कम से कम मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली है। मेरे हृदय को इससे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं, गलियों और मुहल्लों में जा करके, कि उनकी अवस्था आज भी उसी तरह से है जैसी ५० साल पहले थी। बहुत सी जगहों में मैं देखता हूं कि उन लोगों की अवस्था दयनीय होती जा रही है। आज उनके पास अपने गांव में न कोई जमीन है, न मकान है। जिस जगह वह बैठे हुए हैं यह भी किसी दूसरे की होती है। जब भी उनके बारे में कुछ कहा जाता है तो जिनकी जमीन में वह रहते हैं वह कहते हैं कि वह लोग हमारी प्रापर्टी में रहते हैं। जब जब चुनाव का अवसर आता है—आजकल कारपोरेशन का चुनाव होने वाला है—मुझे गांवों में जाने का मौका मिलता है। जब मैं हरिजनों से जाकर कुछ कहता हूं तो वे कहते हैं कि हम लोग जिनकी जमीन में बैठे हुए हैं, बताइये हम उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं और जब जब हम गये हैं हमें ताड़ना दी गई है। रामनाथपुरम् आप के सामने है। वहां हरिजनों का कुसूर क्या था? वह यही था कि उन्होंने एक पार्टी को खुले दिल से वोट किया और उसके विरोध में जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनको ताड़ना दी। इस सदन के सामने पहले भी यह चीज आ चुकी है और उसके ऊपर विवाद हो चुका है। तो यह कुछ कठिनाइयां हैं जो हमारे हृदय को ठेस पहुंचाती हैं।

एक माननीय सदस्य : वह रिजर्वेशन से भी दूर नहीं हो सकता।

श्री नवल प्रभाकर : जरूर होंगी। हम कई बार मन में सोचने लगते हैं कि ठीक है, छुआछूत मिटती जा रही है। जब हम नई दिल्ली में घूमते हैं तो सोचते हैं कि छुआछूत मिट गई है, लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारी यह धारणा बिल्कुल गलत साबित होती है। हमारे भाई ने कहा कि अगर

[श्री नवल प्रभाकर]

रिजर्वेशन दिया जाय या और आगे बढ़ा दिया जाय तब भी ऐसी ही अवस्था रहेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उस जमाने की कल्पना कीजिये जिस में हमारी परछाई से लोग डरते थे। हमारे बच्चों को देख कर लोग घृणा करते थे और जब हमारी परछांई पड़ जाती थी तो उनको स्नान करना पड़ता था। आज वह अवस्था नहीं रही है। परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन जितना परिवर्तन होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। इस बात को आपको मानना पड़गा कि शनैः शनैः सब काम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस को दस वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय तो पिछले दस वर्षों में जितना कार्य हुआ है, आगामी दस वर्षों में उससे आगे होगा और मैं समझता हूं कि हम उस में और तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अन्य लोगों के बराबर पहुंच जायेंगे।

इसके साथ ही मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। दस वर्ष के बाद भी इस तरह होना चाहिये कि जब से दस वर्ष आरम्भ हों, देखना चाहिये कि उस में हरिजनों में कितना प्रचार हुआ। जिन्होंने ज्यादा तरक्की की है, उनको हरिजनों में से या आदिम जातियों में से निकाल देना चाहिये और पिछड़े वर्ग में डाल देना चाहिये। जिस तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधायें मिलती हैं उसी तरह से उन्हें भी मिलनी चाहियें। बाकी बचे हुए जो हरिजन या आदिम जातियों के लोग हैं वे पहले की ही तरह से इसका लाभ उठाते रहें। जब उनमें से कई जाति या वर्ग तरक्की करें, तो उसके लोगों को भी पिछड़े वर्ग में डाल दिया जाय।

मेरी सरकार से यह विनम्र प्रार्थना है और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन है जिसकी अवधि दस साल के लिये बढ़ाने के लिये कहा जा रहा है यह बिल्कुल सही है और मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: I now call Shri Manaen from West Bengal. Mysore will be called next.

Shri Manaen: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Resolution that is before the House is of paramount importance and I think this opportunity must be fully availed of to review the entire aspect of welfare and well-being of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

What was the main idea and the main purpose that was uppermost in the minds of the framers of our Constitution when they made this provision of the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament and the Legislature? If we deduce that all they wanted was to ensure the importation of a few lucky and fortunate members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament and the Legislature, then I will say that we have missed the point by a very great margin.

16 hrs.

Reservation of seats, I think, is only a facade of the problem. The problem, I think, is the misery, backwardness, filth, inhibition, psychological morass in which the privileged section of society had pushed them and kept them there for centuries by social pressures of all varieties. In my humble opinion, the provision in the Constitution is there partly to pay the price for the sin, this particular sin of pushing them down into the deep chasm.

Besides that, I also feel that the main idea behind this provision was to lift up these down-trodden people, these people who were down in the bottom, and give them a chance to live like human beings and to raise them to the status of those favoured by social laws or who have had an opportunity in life.

We have discussed in this House today whether or not we should extend the date of reservation. I feel

that this question should be viewed in the light of what we have achieved during the past few years. The question is, have we succeeded in raising the standard of the common man belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Except for the fact that we have elevated a few selected persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the membership of Parliament and to the Legislatures or perhaps to a higher pedestal, I do not think we have been able to do much for the common man.

The time at my disposal is very short. I only wish to ask why we should cross this bridge before we reach it. Why can't we today, instead of discussing this resolution for extension of reservation, not have a declaration made solumn in this august House that we shall, within a stated period, wipe out the conditions which necessitate the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? The hon. Home Minister was very right when he said in the Rajya Sabha in reply to the debate on a similar type of resolution on the 28th that the present arrangement will continue till 1962 and that the question at present is not important or urgent. I believe the question is not urgent, in so far as reservation of seats is concerned. Because, reservation of seats alone will not bring salvation to 80 million people who are termed as Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This only highlights the burning problem, which I think is not the problem only of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but also the problem of the entire nation .

16.03 hrs.

[SHRI C. R. PATTABHI RAMAN *in the Chair*]

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes constitute an important limb of the nation. A diseased limb is not only annoying, it can affect the whole body. A small sore can develop into gangrene. I am very happy the hon. Mover of the Resolution Shri Deen Bandhu Parmar has brought this Resolution before the House. It is an opportunity for us to renew our determination with a sense of urgency to lift the down-trodden, the depressed and oppressed our brothers and sisters.

As I said earlier, reservation alone will not bring salvation. What is required is to bring them out of the bog, inhabition, fear and doubt. As I was listening to one of the Members. I was surprised. He struck a deep note of inferiority complex. That is very true. What the members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are suffering from is a kind of inferiority complex. What is required is to fire them with a sense of confidence and a sense of self-respect. What is actually required is education and economic emancipation as one of my friends pointed out here. We have enough programmes, we have enough schemes. I would appeal to the government let us for a change try to implement at least 50 per cent of these schemes. Let me not be misunderstod. I do not mean that we should conceive of more Schemes to implement 50 per cent of the Schemes I suggested. I do not mean that. Let us cut the vicious circles. Every time I think of a scheme or we want to bring up a scheme, we immediately conceive of another scheme.

When we read the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, cursorily and when we see the various photos printed there, we are led to believe that the millennium has drawned for these people. I do not thin the correct picture has been drawn there. A large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe people are agriculturists. The achievement of physical targets in this direction has

[Shri Manaen]

not been mentioned in the report. I do not intend to cast any aspersions on the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not wish to do so. I realise that a very great responsibility has developed on him and on his machinery. The Government of India, he one of my friends pointed out, have been very generous. They could not be more generous. They have sanctioned Rs. 39 crores in the first Plan and Rs. 91 crores in the Second Plan for the benefit of the depressed classes. What is required is the gearing up of the machinery to a higher pitch of awarness.

The most important unit in the whole administration, I feel, is the District Welfare Officers. The District Welfare Officers are what may be called the ears, the eyes and the nose of the Commissioner. If these senses are defective, our actions are bound to be blind and insipid. Let us gear up the District Welfare Offices to a higher pitch of efficiency. It should also be required of the District Welfare Officers to submit progress reports every month. An overall evaluation of the welfare activities among the Scheduled Caste and Schedule Tribe people should be required.

I have practically covered all the points that I wanted to stress. I strongly support the Resolution of the hon. Mover. In doing so, I would appeal to the House and also the hon. Members that we should not only think in terms of extending the date. I feel that this is a very platitudinous attitude. Even if we extend the date to the end of the world, if we take this attitude, it may help in the importation to Parliament of a few selected persons, but, we shall not be able to do anything in the way of bringing up these depressed people.....

Shri Thimmaiah: They are extending untouchability.

Shri Manaen: I do not know what my hon. friend is trying to say. What I am trying to say is, that I support the Resolution fully and heartily because I feel that the nation and the country owes a duty to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. I do not want to take any more of the time of the House.

Mr. Chairman: Shri D. A. Katti of Mysore.

Shri D. A. Katti (Chikodi): Shri Siva Raj may speak, Sir.

Shri Thimmaiah: I shall speak for Mysore.

Mr. Chairman: I have a list where it is said, Mr. Katti of Mysore. If he is not here....

Shri Thimmaiah: I shall speak for Mysore.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: Order, order. There is a regular scheme about speakers—people who have not had a chance, with regard to the various lists. You may take it from me, I will read out the names. I have got two others who have already been informed. If Mr. Katti is not here, Shri Yadhav.

Shri D. A. Katti: As Secretary of the Republican Party, I had given the names of Shri B. K. Gaikwad and Shri Siva Raj. Shri Siva Raj may be called on to speak.

Shri Siva Raj (Chingleput—Reserved—Sch. Castes): My name has been given by the Party.

Mr. Chairman: I have noted down your name. The next speaker will be Shri Yadav.

Shri Thimmaiah: Mysore's chance cannot go to Madras.

Mr. Chairman: Fortunately, it is India. I think we should stop thinking of Madras and Mysore. The Scheduled Castes' problem is common throughout the country.

Shri Thimmaiah: The Deputy-Speaker was regulating the debate according to this.

Mr. Chairman: I am following his list.

Shri Thimmaiah: But, Shri D. A. Katti's chance cannot go to Shri Siva Raj.

Mr. Chairman: Shri Yadav.

श्री यादव : सभापति महोदय, यह जो संकल्प है उसका मैं आम तौर से समर्थन करता हूं। आज इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि हरिजनों और आदिम जाति के लोगों के लिये लोक-सभा और असेम्बलियों के अन्दर जाने के लिये दस वर्ष के लिये और संरक्षण मिलना चाहिये। परन्तु जब मैं इसका समर्थन करता हूं तो इसके साथ साथ इस माननीय सदन के सदस्यों और विशेष रूप से अपने सामने बैठे हुये हरिजन बन्धुओं से यह निवेदन करता हूं कि वह इस पर भी ध्यान दें कि यह संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार से हरिजन, आदिम जातियों और मैं तो जोड़ना चाहता हूं कि पिछड़े हुये वर्ग के लोग, जो सदैव से पीड़ित चले आ रहे हैं और जो असमानता के शिकार रहे हैं, उनको संरक्षण की जरूरत है। उस ओर से, इस समय तो वह माननीय सदस्य नहीं हैं, श्री गायकवाड़ के ऊपर यह आक्षेप किया गया था कि वे जो इसका विरोध कर रहे हैं वह अपने राजनैतिक स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। मैं उस आक्षेप का उत्तर देना चाहता हूं।

अगर सरकार ने हरिजनों को उठाने का प्रयत्न किया होता और यह संरक्षण इसलिये दिया होता कि इससे हरिजनों की दशा सुधरेगी तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये था कि वह हरिजन जो शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से सम्बन्ध रखते हैं और जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उनको नौकरी आदि की सुविधा देते तो यह मालूम होता कि हरिजनों की उन्नति करना चाहते हैं। पर जो हुआ है उससे तो यही कहा जा सकता है कि हरिजनों की अवस्था सुधरी नहीं है। लेकिन यहां तो प्रश्न रिजर्वेशन का किया जा रहा है। इधर से नहीं उधर से। यह लांछन बिला वजह हम पर लगाया जा रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिन हरिजनों ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया है क्या ऐसा करने मात्र से उनकी परिस्थिति में कोई तबदीली हो गई है? क्या उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी हो गई? नहीं कदापि नहीं हुई। तब इस ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया। तो जब यह स्थिति है तो मैं कहता हूं कि संरक्षण मांगना कहां तक ठीक है। अगर यह कहा जाये कि संरक्षण मात्र से काम चल जायेगा तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर कुछ विधान सभाओं में और इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों के आ जाने से या कोई हरिजन मंत्री हो जाने से समस्या का हल नहीं होता। हरिजनों की दशा वैसी ही रहेगी।

इस माननीय सदन में आदिम जाति और हरिजनों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उस पर बहस की गई। उस रिपोर्ट से भी यही मालूम होता है कि इन लोगों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। हरिजनों के पानी पीने के लिये कहीं कहीं कुयें बनाये जा रहे हैं, कहीं मकान बनाने के लिये सीमेंट दिया जा रहा है। परन्तु ये तो लड़के को खिलौना देने के समान है, और क्या है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप चाहते हैं कि कुयें न बनाये जायें।

श्री यादव : कुयें बनायें जायें लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहियें। मंत्रियों

[श्री यादव]

के होने से काम नहीं चल सकता । मैं तो कहता हूं कि अगर कोई डा० अम्बेडकर जैसे लोग होते जो कि अपनी योग्यता से आत्म सम्मान से मंत्री बने होते तो मुझे आनन्द होता । लेकिन आज तो चाटुकारिता के नाम पर, और ऊंची जाति वालों और कांग्रेस पार्टी की खुशामद करके गद्दी पर बैठने में हरिजनों के लिये सम्मान की बात नहीं है । क्या है आज ? पुराने जमाने में जमींदार भी अपने पुराने, नाई, धोबियों को अच्छे काम करने के ऐवज में कभी कभी जमींदारी वगैरह चीजें दे दिया करते थे । वह उसी के समान है । अगर स्थिति में सुधार करने का प्रश्न होता, तो इस विषय में ठोस कदम उठाये जाते । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजन तो अपना अधिकार मांगते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है । मैं मानता हूं कि हरिजनों, आदिम जातियों और पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत है और उनकी स्थिति भी बहुत खराब है । तो क्या मांग करनी चाहिये थी ? मांग यह करनी चाहिये थी कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाये । हम हरिजनों को लें । आज हरिजनों के पास खेती नहीं है और अगर है, तो अलाभकर जोत है । अगर प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया होता कि जितने हरिजन अलाभकर जोतों पर काबिज हैं, उनका लगान माफ कर दिया जाता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति में डेफ़िनेट और निश्चित सुधार हुआ होता और वे आगे बढ़े हुये होते । हरिजन और आदिवासी लोग देहातों में मजदूर भी हैं, खेतों में काम करते हैं। आज केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऐसा कानून बनाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है जिस के अनुसार उनकी मजदूरी निश्चित की जाय और केवल निश्चित ही न की जाय, उनको वह मजदूरी दिलाने की भी कोशिश की जाय । केवल कानून पास करने से ही नहीं होगा । हमारे संविधान के आर्टिकल १६(४) और आर्टिकल ३३५ के अनुसार अगर सरकार चाहे, तो वह हरिजनों और आदिवासियों की नौकरी के लिये व्यवस्था कर सकती है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । अगर इन लोगों को हर जगह नौकरी में, खेती में और रोजगार में काम नहीं मिलता है, तो फिर अनटचेबिलिटी आफ़ेन्सिज़ एक्ट से या संविधान में कुछ दफायें बढ़ा देने से काम नहीं होगा । अनटचेबिलिटी आफ़ेन्सिज़ एक्ट आज मौजूद है, लेकिन हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिम-जातियों की रिपोर्ट में देखते हैं कि इस बारे में जिन्होंने ज्यादतियां की, उन पर बहुत कम मुकदमे चलाये गये—दो चार मुकदमे हैं इस तरह के । असलियत क्या है ? असलियत यह है कि जिन लोगों के हाथों में कानून को लागू करने की शक्ति है, वे हरिजन, आदिम जाति और पिछड़े वर्गों के लोग नहीं हैं, वे दूसरे लोग हैं, जिनको इसमें विश्वास नहीं है—विश्वास है इसमें, पर केवल मात्र भाषण करने तक और यह कहने तक कि सब भाई हैं, सब बन्धु हैं, अब हिन्दुस्तान आगे बढ़ गया है । वास्तविकता में उनका कोई तात्पर्य नहीं है । मेरा ख्याल है कि ६०, ६५ हरिजन माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी की ओर से भी चुन कर आये हैं । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि क्या उनमें यह शक्ति नहीं है कि जमीन का बंटवारा करो और जो लोग अपने हाथ से जमीन जोतते बोते नहीं हैं, उन से छीन लो ।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कर सकते ।

श्री यादव : वे सरकार से यह मांग करें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिम जातियों की सीटें रिजर्व न हों, बल्कि जो थोड़े आदमी

इस पद हुआ है, उनकी जगहें रिजर्व्ड हों, तब यह समाज आगे बढ़ेगा । जो प्रस्ताव इस समय हमारे सामने है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं । यह पास होना चाहिये, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव लाना तो एक राजनैतिक चाल है । श्री बाजपेयी ने कहा कि वह रिज़र्वेशन के उसूल को तो मानते हैं, लेकिन पांच और दस साल में कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई बड़ा अन्तर नहीं होता है । अन्तर क्यों नहीं होता है, यह तो बाजपेयी जी ही बेहतर जानते होंगे । लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर छः आदमी जनरल सीटों से चुन कर आये हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव कमीशन यह व्यवस्था करता है कि कोई डबल-मेम्बर कांस्टीच्युएन्सी नहीं होगी, हरिजनों के लिये सीट रिजर्व्ड होगी, तब पता चलेगा कि वे कैसे आते हैं । हमारे यहां कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो कुछ वोट बढ़ जाने के कारण ही यहां आ गये हैं । इसी सदन के एक सदस्य और अब गवर्नर, श्री गिरी के खिलाफ़ हमारी पार्टी के एक हरिजन साहब जीत कर आ गये हैं । वे इसलिये नहीं आ गये हैं कि लोगों के मन का भाव बदल गया और उन्होंने उनके मुकाबले में इनको वोट दिये ।

श्री बाजपेयी : उन के जीतने से यही प्रकट होता है ।

श्री यादव : जो यहां पर ६० आदमी जीत कर आये हैं, वे दूसरे के कांधे पर लद कर आये हैं और उनकी मनचाही बात करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : कन्धे पर रख कर लाये हैं ।

श्री यादव : जहां तक छुआछूत का सम्बन्ध है, जब तक आपस में शादी-ब्याह के सम्बन्ध नहीं होते, तब तक उसका दूर होना कठिन है और शादी-ब्याह तब तक आर्थिक दशा नहीं सुधरती है और उसको सुधारने के लिये कदम नहीं उठाये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य ने बैकवर्ड के कई क्लास ही बना दिये अर्थात् एक दर्जे से बढ़ कर दूसरे दर्जे में रख दिया जाय, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में रख दिया जाय, इत्यादि । न जाने किस तरह के भाव ये लोग प्रकट करते हैं । इनसे क्या आशा की जा सकती है ।

पिछड़े वर्ग का एक आयोग बिठाया गया । उसने सारी जांच की और रिपोर्ट दी । अगर सरकार की हिम्मत होती, तो वह रिपोर्ट, पर बहस करवा देती, लेकिन वह इसके लिय तैयार नहीं है । केवल रिजर्वेशन मात्र से काम नहीं चलेगा । वह हो, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार पर—इस समाजवादी ढंग की सरकार पर, जो कि मेरे दृष्टिकोण में असमाजवादी है और जो केवल वोटों के लिये ही कार्य करती है, ज़ोर डालने से ही काम चलेगा । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

Shri Thimmaiah: The Scheduled Caste people in this country have been treated as untouchables since immemorial times. They were socially suppressed, economically exploited, politically not encouraged. Even in this modern age in this country in 99 per cent of the villages, 99 per cent of the Scheduled Caste people are treated as lepers, as untouchables, and they do not enjoy the other privileges that the caste Hindus enjoy in the villages. They cannot have freedom of movement and freedom of living in the villages. They are not allowed to enjoy the common amenities in the villages; they are not allowed to take a marriage procession on the road. In 99 per cent of the villages,

[Shri Thimmaiah.]

This untouchability has hindered our progress, and it has suppressed our spirit so much that we cannot assert ourselves. This is the position in which we are even in this modern age, even in the year 1958. When that is the case, how can we contest in the general elections and compete with the general candidates and win the elections? It is for the House to judge.

I said that this untouchability has hindered our economic development because the cast Hindus in the villages never encourage us in the proper manner. They feel jealous of our economic prosperity. If any lands are given to us, they feel jealous of us, and they put all sorts of impediments in our way to see that we do not get our lands. They want that we should be dependent on them always, and they want that our economy should depend on them. We are in a sense agricultural slaves in the villages. At least that is the position in the case of a majority of our people. When that is the position, it is impossible for us to compete with the general candidates and win the elections. So, I say that the reservation should be continued for another ten years.

It is because this reservation was there that we were able to get into this House in large numbers. But what about those bodies where there is no reservation? Take, for instance, the Council of States. There, we are not at all represented. Not even one per cent of our Members are represented in the Council of States; the same is the case in respect of the Legislative Councils in the States also. Similary, in the case of the Central Cabinet and the State Cabinets, they do not give us adequate representation in proportion to our population. If the suppressed classes of any country have to prosper, then they will have to be given their due share in political power and position and they should have their due share in the administrative services of the country. For the sake of political power and administration, for getting their due share in the body-politic, we have seen how the Plebeians and the Patricians fought in the good old days. But we the Scheduled Caste people are not of that type to fight with Government or to fight with the people in this country.

We have been in this country faithful to the society, served their purpose and even today we serve them more or less as slaves. But when the question of power and position comes, we are not given full justice. We the teeming millions of the Scheduled Caste people and the backward people have to produce food for the country, and we will have to work on the agricultural fields, and we will have to sacrifice our life for the country, if the time comes, at the war front also, but what is the encouragement that we get from our Government and our leaders when the question of power and position comes up?

The reservation of a 12 per cent quota in Government services is merely on paper, and it is not at all implemented. Therefore, I say that at least to enable us to raise our meek voice in the Lok Sabha, at least to ventilate our grievances in the Lok Sahba, we want that this reservation should continue. Is that any big demand?

One hon. Member from the Opposition told us that this reservation has enslaved us. But that is not worse than the slavery that we were enjoying before the reservation came into operation. So, I say that whatever difference it might make, we want to have this reservation for another ten years, so that we may raise our voice in this Parliament.

In the Councils of Ministers in the States also, the Scheduled Caste people have not been given adequate representation. In fact, I met one or two Chief Ministers of States, and I asked them 'Why don't you give us adequate representation in the Cab-

inet? ' And one of them said, 'Why don't you ask your Prime Minister to give you adequate representation in the Central Cabinet? I could not answer that question. Another Chief Minister said, 'I want to give seats for Harijans, I want to give them proportional representation in the Council and also in the Cabinet, but the Centre does not permit me to expand my cabinet.'

Shri M. R. Krishna: Permit?

Shri Thimmaiah: Yes. He said that the Centre did not permit him.

This is the plight of our people in the bodypolitic and in Government. We are grateful to Government to the extent that we have got this reservation. If we did not have this reservation, our number even in the Lok Sabha would have been less, and we would not have been represented fully in the House. Therefore, I submit that this reservation may be extended without any prejudice for another ten years.

There is a section of people in this country who think that this reservation will develop a separatist mentality. But if you read history, it will tell you who the separatists are, who the communalists are, and who encourage communalism. You will find the answer in the pages of hissory.

Shri Siva Raj: This Government is a Hindu Government.

Shri Thimmaiah: It is we the Scheduled Caste people who have suffered from the evils of separatism and Hindu imperialism; and it is they who are preaching us today broadmindedness. So it is but proper that they should prove that they are not communalists. It would be seen from history that it is not the Scheduled Caste people who betrayed this country, but it was the others who betrayed this country. You can read this whether in mediaeval history or in the history of the Mughal period or anywhere else. The Scheduled Caste people were loyal to the country, and it was only the others who betrayed this country to the foreigners for their own selfishness. Even today, if you give political privileges and full power to the Scheduled Caste I am sure they will be the persons who can do justice to every section of the community. They are not mad after excess of power; they are not mad after monopolising every position; they are not mad after cornering every power. I say this in all seriousness and sincerity, so that my people in this country who form the weak link today, namely the Scheduled Castes, may prosper and live with the others as good citizens.

Mr. Chairman: Now, Shri Siva Raj.

Raja Mahendra Pratap (Mathura): May I also speak?

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, हम महिलाओं को भी बोलने का अवसर दीजिये।

Shri Nath Pai (Rajapur): We support her demand wholeheartedly.

Mr. Chairman: I have called Shri Siva Raj now.

Shri Siva Raj: Obviously, it is natural for those who have tasted office and power through reservation of seats to hang on to it and fight vehemently for it. But the very object of the provision in making the method of representation for the Scheduled Castes in the Constitution was to see that the representation of the Scheduled Castes was such that it was adequate and effective. At a time when this question was seriously discussed—and it has been discussed for a long time since the days of the Simon Commission—the idea of representation for the Scheduled Castes was accepted, but the method of representation was in dispute. My friends now deny, what Mahatma Gandhi suggested. He said at the round Table Conference that he was the sole representative of the Scheduled Castes, and as such the

[Shri Siva Raj]

Scheduled Castes need have no representation at all in the Legislatures. But our friends here who claim him to be the Father of the Nation and who claim him to be their redeemer seem to give a lie direct to the opinion of Mahatma Gandhi. I am rather surprised that that should be so in a party which always claims that it is following the food-steps of the great leader.

In the first place, the article is mandatory, and in order to change the provisions of that article, Government must put forward a very strong case for changing that article. I do not think Government can do it. The fact that in other respects the Scheduled Castes have not come up as much as was expected on account of the various measures taken by various governments, both at the Centre and in the States, cannot be an argument for the continuation of the reservation of seats. According to me, according to the Members of my way of thinking and according to the late lamented Dr. Ambedkar, reservation of seats has operated as a stranglehold on the political growth and life of the Scheduled Caste people. Literally, it put the lid upon their growth as full citizens of this country. Every time, they stood for any election, they have had to go with a begging bowl to any political party which is powerful in that political area. This will never bring us, the Scheduled Castes, to the status of political citizens of this country. That is one of the handicaps of reservation.

Moreover, I personally think that with a view to develop parliamentary democracy this representation of particular communities like the Scheduled Castes and others will operate as a drag on the growth of real parliamentary traditions and the growth of parliamentary government in this country.

Honestly speaking, with all that is said in favour of the Congress Party, what does one find? The Congress Party is really speaking, a party of the majority community with a sprinkling here and there of minority communities like a Christian or a Scheduled Caste man. Actually it is a Government, in my opinion, at any rate— I am subject to correction—as I see it, of the Hindus, for the Hindus and by the Hindus, except in the case of Mohammedans. I suppose there they are actuated by a feeling of fear of the Mohammedans or by the feeling that they have got support elsewhere other than India, and so they are amenable to the wishes or the threats of the Mohammedan element of the Indian population. This is obvious from the way the Government is constituted at the present moment.

So far as we are concerned, we have laid it as our political opinion and our political programme that we are not anxious to get into office or power. But we are anxious to see that no Government is put in power which will run against our interests and our further growth. I personally think that the continuation of this reservation of seats will be an insult to the dignity of representatives of Scheduled Castes in this House or to the dignity of any other representative in this country. Whenever a person comes from a reserved seat, he is treated in a slightly inferior position. 'After all, he has come from a reserved seat'—that sort of superiority complex is there towards the persons coming from the reserved seats.

With these words, I oppose this Resolution.

Raja Mahendra Pratap: May I say a few words?

Mr. Chairman: Shrimati Sahodrabai. I want to impress on Raja Mahendra Pratap that we have got a regular list.

Raja Mahendra Pratap: These Members want me to say a few words.

Mr. Chairman: I have no doubt many people want him to speak, but

the real trouble is that we have got a list prepared.

श्रीमती सहोदरा बाई : सभापति महोदय, आज जो प्रस्ताव शैड्यूल्ड कास्ट्स तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में रखा गया है, इसको अगर कानून है तो पास किया जाये और अगर कानून नहीं है, तो इसको वापिस ले लिया जाये । १९६२ तक तो रिजर्वेशन है ही । इस वास्ते अभी इस बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं । (*Interruption*) मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे बीच में आप लोग न बोलें और जब मैं बोल चुकूं तब आप बोलें ।

सभापति महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने जो यह रिजर्वेशन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव रक्खा है उसके लिए मेरा कहना है कि यह सुझाव छुआछूत हमारे पुरुष समाज के अन्दर उतनी नहीं है जितनी कि महिलाओं के अन्दर है और यह छुआछूत की भावना हरिजन और सवर्ण दोनों में है । यदि कोई पुरुष किसी हरिजन के साथ कांग्रेस वर्क के सिलसिले में उठना बैठना है तो उस पुरुष की स्त्री उस से कहती है कि मेरे कपड़े मत छुओ और मेरे पलंग पर मत सोओ, तुम हरिजन को छू कर आये हो । इसलिये मेरा कहना है कि जब तक अपनी महिला समाज से इस छुआछूत की भावना को नहीं मिटावेंगे तब तक इन हरिजनों का कभी कल्याण नहीं हो सकता है । हिन्दुओं में सवर्ण जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य तो हैं ही और वे तो हरिजनों के साथ छुआछूत बर्तते ही हैं लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हरिजनों की जो ७५ के क़रीब जातियां हैं उन में आपस में भी एक दूसरे के प्रति भेद भाव और छुआछूत बर्ती जाती है । चमार के ऊपर दूसरी चमार जाति होती है और हम देखते और मेहतर वसोर से विरोध करता है, आपस में जब इन जातियों में एक दूसरे के साथ छुआछूत और भेद भाव बर्ता जाता हो तब यह समस्या कैसे हल हो सकती है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज जो हरिजनों की उपजातियों में आपस में छुआछूत चलती है वह खत्म होनी चाहिए ।

मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि पिछले तीस सालों से मैं हरिजनों की सेवा करती आई हूं और मुझे मालूम है कि कई ऐसे हरिजन लोग हैं जो कि बंगाल (नौआखली) गये और गोवा गये और उन्होंने हरिजनों की बहुत सेवा की है उन लोगों को इस जातिवाद के कारण छोड़ दिया गया है और न तो उनको टिकट मिला है और न उनकी सेवाएं ली जा रही हैं । उनको न तो लोकसभा के लिए और न ही विधान सभाओं के लिए टिकट मिला है और उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है और यह सब इस कारण हो रहा है कि हर जगह जातिवाद का बोलबाला है और इसी कारण लोकसभा और विधान सभाओं में हर जगह पर चमार जाति के लोग आगये हैं । इस तरह का हरिजन-हरिजन में भेदभाव करना एकदम अनुचित है और मेरा कहना है कि सब हरिजनों को एक समान मानना चाहिए ।

आज हम देखते हैं कि जातिवाद का भेद हमारे अंदर इतना घर कर गया है कि चमार-चमार में भी भेदभाव बढ़ता जाता है और सतनामी चमार, जाटवा चमार, ऐबरवार चमार और मेहरा चमार आपस में एक नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहता है और अपनी जाति का पक्ष लेता है और इस तरह भेदभाव की नीति बर्तता है । हमने देखा कि श्री कजरोलकर ने शेडयूल्ड कास्ट्स का हल निकाला था उसमें

[श्रीमती सहोदरा बाई]

झंडे दिखाये और इसलिए दिखाये कि तुम्हारी पार्टी ठीक नहीं है और तुम्हारी नीति ठीक नहीं है। मेरी बात का बुरा न माना जाय, मैं जरा बुलन्द आवाज में बोलती हूं लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वह सही रूप में हरिजनों में जो आज हालत है उसको दर्शाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हरिजनों हरिजनों में आपस में जो छुआछूत और भेद-भाव वर्ता जाता है उसको दूर करना चाहिए और जब तक वह दूर नहीं होती तब तक हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि जहां पर एक रिजर्वड सीट होती है वहां हरिजनों में आपस में तरफ़दारी होती है और एक सीट के पीछे सारी जाति के हरिजन लोग आपस दौड़ पड़ते हैं और ऐसे दौड़ते हैं जैसे गाय के पीछे कौवे। हम देखते हैं कि एक जाति के सिवा दूसरी जाति के हरिजनों को को टिकट नहीं मिलते हैं और हमने यह भी देखा है कि अगर कहीं दूसरी जाति के लोगों को टिकट दे दिया गया तो वे लोग कांग्रेस से स्तीफा देकर उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब लोक-सभा में एक गैर चमार महिला जो आगई तो उसके पीछे काफ़ी हरिजन चमार लग गये कि उसे किसी तरह यहां न आने दें और जैसे भी हो उसको हरा दें। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कहां तक उचित है? इसी तरह मैं बताऊं कि एक सज्जन जो कि ६ साल मिनिस्टर रहे और फिर राज्य सभा के मेम्बर रहे, अब चूंकि उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसलिए विरोध में खड़े हो गये। आखिर यह कहां की नीति है? इसी तरह हम देखते हैं कि हरिजन उद्धार के कार्यों पर जो पैसा दिया जाता है वह ठीक तौर पर खर्च नहीं किया जाता है और उस में भी तरफ़दारी वर्ती जाती है।

मैं ने आपका बहुत समय ले लिया है इसके लिए माफ़ी चाहती हूं लेकिन मैंने आज जो सच्ची स्थिति हरिजनों में है वह यहां हाउस के सामने रख दी है।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि अभी अगर 'शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोई कानून है तो इसको पास किया जाय और अगर कोई कानून नहीं है तो इसको वापिस किया जाय।। सन् १९६२ तक इसकी मियाद है इसलिए इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है।

जैसा मैंने शुरू कहा मैं फिर इस चीज को बिलकुल साफ़ कर देना चाहती हूं कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्री यह सवर्ण हिन्दू लोग तो हम हरिजनों और आदिवासियों के साथ छुआछूत वर्तते हैं ही लेकिन हम हरिजनों की जो ७५ और अनेकों जातियां हैं उन में भी आपस में एक दूसरे के प्रति भेद भाव वर्ता जाता है और छुआछूत वर्ती जाती है और विधान सभाओं और लोक सभा में टिकट देने में भी जातिवाद वर्ता जाता है, जो कि सर्वथा अवांछनीय है और जिसके कि रहते हमारे लिए यह कानूनी व्यवस्था और रिजर्वेशन बेमानी हो जाती है। आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम इस जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत जो हमारे अपने बीच में विद्यमान है, उसको हटाये और तभी हरिजनों का वास्तविक अर्थ में कल्याण हो सकेगा। आज तो हम बिलकुल उसका उल्टा देखते हैं और चमारों के नाम पर यह भेदभाव होते देखते हैं...

Shri P. L. Barupal: On a point of order, Sir...

श्रीमती सहोदरा बाई: आप चुप रहें, मुझे बोलने दें.....

Mr. Chairman: Order, order. I would request the hon. Member not to proceed like this. We must preserve order in the House.

श्रीमती सहोदरा बाई : सभापति महोदय, यह बीच में बिना आपकी आज्ञा के क्यों विघ्न डालते हैं । सही स्थिति बताने वाला हरिजनों को बुरा लगता है । क्यों बुरा लगता है ? हम चार वर्ण के लोग हिन्दुस्तान में हैं, जब हम चारों ही रोटी बांट कर नहीं खा सकेंगे तो कैसे काम चलेगा । हम पार्टियों में भोजन के लिये जाते हैं, हम चमार की पत्तल उठा कर फेंक देंगे पार्टी में, लेकिन चमार हमारी पत्तलें नहीं उठायेगा । मेहतर नहीं उठायगा वाह यह नहीं आप देखिये कि ब्राह्मण और ठाकुर रोटी खा लेते हैं बैठ कर, लेकिन हरिजन हरिजन के पास बैठ कर रोटी नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता । तो भला बताइये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की स्थिति कैसे ठीक हो । मैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के विरोध में नहीं बोल रही हूं लेकिन जब तक वह मिल कर नहीं चलेंगे तब तक स्वराज्य कैसे कायम होगा ? वे लोग सही स्थिति सदन के सामने नहीं रखते हैं, केवल ब्राह्मणों, ठाकुरों और दूसरे लोगों को दोष देते हैं । अपनी नहीं कहते हैं कि उन में क्या दोष हैं, हम में कितनी जातियां हैं, हम में क्या सुधार होना चाहिये । यह सीट कोई हमारी बपौती नहीं है, यहां सब को आना चाहिये, यह देश का काम है । आज होता क्या है कि जैसे गाय के मुख से कौवा या चील रोटी छीन ले जाती है वैसे ही हरिजन हम से सीटें चाहते हैं । आज अगर एक हरिजन जनरल सीट से खड़ा हो जाय तो जीत नहीं सकता । वह लोग आज रिजर्वेशन ले कर कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाते हैं । यह नीति है।

मैं पूछती हूं कि आज से दस साल पहिले हरिजनों की क्या हालत थी ? हम लोगों के जूतों के पास बैठते थे, अंग्रेज लोग उनको अपने पास नहीं आने देते थे । मगर आज चूंकि हमारी गवर्नमेंट है, आज वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बैठ सकते हैं, उन के साथ रोटी खा सकते हैं । आज स्थिति ऐसी है कि अगर हम लोग हरिजनों के पास जायेंगे तो हमें जूतों के पास बैठना होगा और वह लोग कुर्सी पर बैठेंगे । अगर उन की इसी तरह से उन्नति होती जायेगी तो एक दिन हमारी यह सीटें भी छिन जायेंगी ।

हर एक आदमी कहता है कि छुआछूत है। यह छुआछूत बन्द कैसे हो ? फलानीचीज कैसे बन्द हो । आज सवाल यह है कि मान लीजिए एक गांव में शादी है । चमार के घर में बरात आती है । आज जब सवाल आता है कि ब्राह्मण और ठाकुर से जा कर पूछो कि हमें दुल्हन के दरवाजे जाना है, आप की इजाजत हमारे जाने की है या नहीं, तो वे कहते हैं कि क्या जरूरत है पूछने की । हाथी पर बैठे हैं । अगर कोई कुछ कहता है तो धत्, धत्, धत् कहने लगते हैं । यह शेड्यूल्ड कास्ट्स की हालत है · चाहिये यह था कि उनसे जाकर राम राम करते । कहते कि मालिक हमें तुम्हारे दरवाजे से होकर जाना है, कहो तो चले जायें । तो वही लोग उनको बन्दूक देते, पिस्तौल देते, खाने का इन्तजाम करते, और सारे बन्दोबस्त करते । लेकिन यह लोग तो कहते हैं कि फलां ब्राह्मण है, ठाकुर है, उसके दरवाजे क्यों जायें । थोड़ा सा उनको सहन नहीं होता, जरा सी बात पर जूते चलाने लगते हैं पट, पट, पट करके । ..

आज वही लोग गांवों से बाहर जा रहे हैं, लेकिन यह जो चाल उन्होंने चली है उसी सबब से है । गांवों में काश्तकार ज्यादा हैं, वह खेती करते हैं, वे ब्राह्मण ठाकुर नहीं स्थिति को जानते हैं ऐसी हालत में वे लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं ? आज वह क्या करते हैं कि जब कोई एम० पी० या एम० एल० ए०, वहां जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम यहां किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करें ? हम शहर की ओर जायेंगे । अगर

[श्री साधू राम]

वह लोग वहां से शहर की ओर भाग गये तो देहातों का क्या होगा । जब शहर बढ़ेंगे तो देहात खत्म होंगे । आज किसान कहते हैं कि हम क्या करें, तुमने हमारा काम खत्म कर दिया, हमारी काश्त का बन्दोबस्त नहीं करते । जमीन पड़ी है । हरिजन लोग कुछ कर नहीं सकते । हम शहर जाते हैं । सिनेमा देखेंगे, बोतल भर शराब पियेंगे । हम क्यों तकलीफ उठायें ? मैं बतलाऊंगा कि जितने रेलवे कर्मचारी हैं, जिनको ४० से ७० रुपये तक मिलते हैं, वह दिन में दो बोतल शराब पी जाते हैं । यह ७० रुपया उसी में खत्म हो जाता है । घर की महिला रोती है बच्चे रोते हैं । वह कहती है कि हम क्या करें, अब कैसे काम चलायें । रात भर वह परेशान होती रहती है । जब यह स्थिति है तो हरिजन लोग कैसे आगे बढ़ें । इसलिये मैं कहती हूं कि यह लोग यहां पर सही स्थिति नहीं बतलाते हैं ।

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे विश्वास रखें कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं । मैंने जो कुछ कहा है देश की परिस्थिति सुधारने के लिये कहा है ।

श्री सापूराम (जालंधर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चेयरमैन साहब, आज हमारे सामने रिजर्वेशन का रेजोल्यूशन आया है । रिजर्वेशन की मियाद बढ़ाने के लिये हमारे परमार जी रेजोल्यूशन लाये हैं । रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग इस देश में था आजादी के बाद, उस को कुछ रियायतें मिली हुई हैं, उनकी सीटें महफूज की गई हैं ताकि वह वर्ग असेम्बलीज और पार्लियामेंट में आकर उन गरीब लोगों की नुमाइन्दगी कर सके और उनको जो सुझाव गवर्नमेंट को देने हैं वह सही तौर से दिये जा सकें । यह रिजर्वेशन दस साल के लिये दिया गया था । अब रेजोल्यूशन आया है कि उसे दस साल और बढ़ा दिया जाय ।

रिजर्वेशन दो किस्मों का होता है । एक तो लेजिस्लेचर्स में और दूसरा सर्विसेज में । हमारे एक भाई यह चाहते हैं कि सर्विसेज में तो रिजर्वेशन कायम रखा जाय और लेजिस्लेचर्स में जो रिजर्वेशन है, उसे खत्म कर दिया जाय । गोया वह लंगड़ा रिजर्वेशन चाहते हैं । दो पावों वाला रिजर्वेशन नहीं चाहते । मैं समझता हूं कि जो देश भर के पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह इस तरीके से ही आगे आ सकते हैं जब कि उनका रिजर्वेशन कायम रक्खा जाय । हमारा देश अभी आगे नहीं बढ़ सका है । हम समझते हैं कि इसमें अभी दस साल के बजाय चालीस वर्ष लगेंगे जब कि देश में बराबरी आयेगी । जिन लोगों का ख्याल है कि पिछड़े वर्ग के लोग बगैर रिजर्वेशन के ही अपनी सीटों पर आ सकते हैं या पार्लियामेंट और असेम्बलीज में अपनी जगहें ले सकते हैं, उनके लिये कोई रुकावट नहीं है, उनसे मैं कहता हूं कि जो सीटें आज रिजर्व्ड हैं उनके लिये वे टिकट ले कर देख लें । वे अपनी पार्टी में पास कर दें कि हम रिजर्व्ड सीट से किसी जगह, किसी असेम्बली या पार्लियामेंट के लिये एलेक्शन नहीं लड़ेंगे । उनको जेनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिये । जो रिजर्वेशन देने की मुखालिफत कर रहे हैं उनको पता चल जायेगा कि उनको खत्म कर देने का असर क्या होता है ।

16.51 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

वह रिजर्व्ड सीट से एलेक्शन लड़ें जो कि रिजर्वेशन को नहीं पसन्द करते हैं । वह जनरल सीट से लड़ें और पार्टी को चलायें । फिर हम देखेंगे कि उनकी पार्टी के लोग कितनी गिनती में असेम्बलियों और पार्लियामेंट में आते हैं ।

मैं महसूस करता हूं कि अभी जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है देश में, वह बहुत कमजोर है । कमजोरी की वजह से दिमागी तौर में,

जिसमें कि वोटों से लोगों का चुनाव होता है, लोग अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे । उनसे बहुत से लोग कई तरीकों से वोटों को हासिल कर लेंगे । जो लोग सही तौर पर उनकी तकलीफों को यहां बता सकते हैं, वह नहीं आ सकेंगे । उन्होंने अपनी तकरीर में एक दावा किया है कि पिछड़े वर्ग के वही असली नुमाइन्दे हैं । शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के इस सदन में ६ नुमाइन्दे हैं । लेकिन आज रिजर्वेशन की वजह से इस हाउस में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के टोटल मेम्बर १०७ हैं । क्या माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के ६ आदमी हिन्दुस्तान के ९ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के असली नुमाइन्दे हैं । बाकी जो हैं वह सब नकली नुमाइन्दे हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

दूसरी बात यह है कि अगर रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाये तो खत्म करने के साथ ही सर्विसेज में भी वह खत्म हो जाता है । अपने मांबों के पढ़े लिखे नौजवानों के मुकाबले उन को यही तो चान्स था । इस देश में हजारों सालों से उन को कोई मौका नहीं मिला । बहुत दिनों के बाद थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर के वह लोग सर्विसेज में गये हैं । क्या उन को यह पता नहीं है कि दूसरे लोगों के मुकाबले में उन को कुछ रियायतें मिली हुई हैं ? अगर कोई हरिजन ग्रादमी मैट्रिक हो और दूसरा कोई हिन्दू या सिख भी मैट्रिक हो तो उन दोनों के मुकाबिले हरिजन को प्रिफरेंस मिलता है । अगर हिन्दू और सिख की तालीम बी० ए० की है और हरिजन की तालीम एफ० ए० तक है तो हरिजन को ले लिया जाता है । तो क्या आप का मतलब यह है कि इस रिजर्वेशन को खत्म कर देने से हरिजन लोग खुश होंगे ? मैं समझता हूं कि अभी भी रिजर्वेशन को कायम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है । यह नहीं कहा जा सकता कि दस वर्ष के बाद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी । बल्कि कहना चाहिये कि शायद दस वर्ष के बाद भी उस की जरूरत पड़े । इस देश में पिछड़े वर्गों के लिये कुछ और सालों के लिये रिजर्वेशन देना पड़ेगा । अगर सब को बराबरी पर लाने के लिये रिजर्वेशन को कायम नहीं रक्खा गया तो जिस तरह पर आप चाहें कानून पास कर सकते हैं, सारी असेम्बलियां और पार्लियामेंट आज कल कानून पास कर रही हैं, आप सोच सकते हैं कि वहां पर इन लोगों की कोई नुमाइन्दगी नहीं होगी । अगर केन्द्रीय सरकार में उन की नुमाइन्दगी नहीं होगी तो मेरा खयाल है कि वह इस पिछड़े वर्ग को और पीछे डालने की कोशिश होगी । मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ठंडे दिल से सोचें ।

दूसरी बात यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि डा० अम्बेडकर की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने यह रेजोल्यूशन पास कर दिया है । क्या वह रेजोल्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने ही पास किया है और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के साथ हिन्दुस्तान भर के लोग हैं । जो कि हरिजन हैं या पिछड़े वर्ग के हैं । तो यह कहा जा सकता है कि वह उसमें हैं ।

दूसरी बात यह है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से रेजोल्यूशन का विरोध है तो वह तो अपने आपको बुद्ध कहने लगे हैं और उन्हें रिजर्वेशन के झगड़े में पड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती । वह तो कुछ चोटी के हिन्दू बन गये हैं या बौद्ध बन गये हैं । वे शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट से निकलना चाहते हैं या निकल गये हैं । तो मेरा ख्याल है कि वे लोग अब इस झगड़े में न पड़ें । जब इलेक्शन आयेगा तो वे जनरल सीट्स पर से लड़ें और जो अब लोक-सभा में बैठे हैं वे लोक-सभा से रिजाइन कर के जनरल सीट से इलेक्शन लड़ें तो उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जायेगा ।

[श्री साधू राम]

मैं इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं ताकि रिजरवेशन जो है वह जरूर बना रहे।

Mr. Deputy-Speaker: I am calling the hon. Minister. I am very sorry I have not been able to give some time for those who yet want to speak. But I am sure they will realise that they would have an opportunity to speak during the debate on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and on the Demands for Grants under the Ministry of Home Affairs. All those discussions will be coming up. Therefore, I shall make it a point and ask the office to prepare a list of those Members who wanted to speak today and have not been given the opportunity to speak, so that they will have the preference and get the first opportunity to speak later and put in their points. I am sorry I could not accommodate the other hon. Members who wanted to speak.

Shri Sonavane (Sholapur—Reserved—Sch. Castes): Will it not be advisable to sit for half an hour more to accommodate some of the Members who want to speak, because this is an important matter?

Mr. Deputy-Speaker: That is all right. But even if I extend the time by an hour, there will be eight to ten Members only who could be accommodated. Not more. Supposing the House wishes to sit for half an hour more, then about four Members could be accommodated, and not all those who wish to speak. There would yet be others who would not get the opportunity, and the same complaint will be made.

Shri Sonavane: It is better to have something than nothing.

Mr. Deputy-Speaker: But the hon. Member may not be able to cover much within that something. He would have the same grouse again.

स्वामी रामानन्द शास्त्री (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या साढ़े ६ करोड़ की है। उसमें से एक को भी समय नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: एक को तो सब से पहले दिया गया और वह ले चुके हैं।

एक माननीय सदस्य: बिहार से किसी को समय नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ने पुकार कर कहा था .....

श्री प० ला० बाक्लीवाल: राजस्थान भी रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय: राजस्थान वाले ने तो मूव ही किया था।

Shri Sonavane: Generally we extend the time and sit longer, for important discussions. This is an important occasion when we can sit for some more time.

Mr. Deputy-Speaker: The only difficulty is this. When the Committe on Private Members' Bills and Resolutions fixed the time, they had in view the aspect that at least there should be one minute left for the next resolution to be moved, so that the Member concerned could not be pushed out. That is the difficulty that I am experieneing. If the House wants to sit for half an hour more, I have no objection, provided the right of that hon. Member is safeguarded. I find that the consensus of opinion of the hon. Members is that they are not prepared to sit longer.

Shri Sonavane: They are for it.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister.

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a very simple and straight resolution asking for more time for reservation in the legislatures of States and in Parliament. However, an identical resolution of this type was moved in the other House last month. It was debated at length and the hon. Home Minister replied, and his reply

was convincing enough, and the Mover, Shri Rajabhoj, withdrew his resolution.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): No suggestion should be made to that effect here also.

Shrimati Alva: I am not making a suggestion.

Mr. Deputy-Speaker: It is a statement of fact.

Shrimati Alva: Once again this House takes up the same subject that has been discussed in the other House, has debated it at length and has disgressed from the main resolution in asking for extension of time to all other aspects of the problem. I do not say that they are not corelated, but this is a restrictive resolution asking for an extension of ten years. Members on both

17 hrs.

sides spoke with passion, and they gathered sympathy from all sides. But it was refreshing to note that the hon. Members. Shri Gaekwad, Shri Siva Raj and some here on this side felt.....

An Hon. Member: Nobody from this side.

Shrimati Alva: I think one member did oppose. They have opposed the resolution for the simple reason that reservation will not solve the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Historically, members went back to the days of Ramsay MacDonald and the communal electorates. Then we must remember the epic fast of Mahatma Gandhi. It was his dream to remove untouchability and to bring them up to the standard of the so-called civilisation and comfort. How is this to be done?

Just a minute ago, it was Maniben who told me that certain things are achieved in a particular way. Sir I may be permitted to be a little irrelevant, because members have said that after Gandhiji took up this problem there is a lull. There may be a lull, because it is not the amount of money or the policy that we lay down that is going to solve the problem. Maniben told me that in Banaskantha they have been able to bring a Harijan lady uncontested for the Local Boardseat. Now, Banaskantha, as far as I know, is the most backward place. Likewise, in Bombay too, they have thrown open the chawl at Worli, where all kinds of people stay. Then, to cut the story short, I come to the only hon. Lady member who spoke in this House in, you may say, a rustic way.

Shri Nath Pai: She spoke in a polished way.

Shrimati Alva: Even a rustic can be polished.

Shri Nath Pai: Is that what you mean?

Shrimati Alva: It is not the monopoly of gentlemen and ladies.

She said it in a rustic way. She showed the evils that exist. I may cite the case of Bombay, where in the chathralays all kinds of Harijans have to get together. What she observed is worth mentioning, for her observations were made in a very direct manner, and they seem to have been made with a fund of experience. I think we should sit and examine those observations.

If we go back to the days when the Constitution was framed for us, we come to this problem of the reservation for minorities. Minorities in the days gone by were not merely Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There were other minorities also—Muslims, Christians and Sikhs. But, the other minorities gave up this right of reservation when the Constitution was being framed, and they are no worse for it.

However, the Government and the framer of the Constitution realised that some sort of representation had to be given to the weaker sections of the society, weaker economically, socially, politically and otherwise

[Shrimati Alva]

And that is why it was laid down in the Constitution primarily to give ten years guarantee. Sardar Patel, who was the President of the Minorities' Committee, convinced them that though it was necessary to give reservation, it was also a fact that reservation cannot remove communal and other differences.

We must bear in mind, as we are progressing in a democratic fashion, that some day or the other reservations will have to go, otherwise watertight compartments are formed and they do more evil than good. But I am not going into the pros and cons of this particular issue. This particular issue will be raised according to the Constitution in 1960, which is the time limit laid down in Article 334 of our Constitution, but our legislatures will be dissolving only in 1962 and those, who are members in 1960 in the legislatures on this provision of reservation of seats, will continue up to 1960. That assurance was given by the hon. Home Minister in the other House (*Interruptions*), but again and again Members have raised this issue. Now, that does not arise till 1962.

However, this question is engaging the attention of the Government because we do feel that the weaker sections have not become strong enough to stand on their own legs. But the assessment has to be made and we are doing that from all sources. You have the reports before you which tell you that the weaker sections remain the weaker sections. The weaker sections may need reservations and safeguards for some more time. That will be engaging the attention of the Government. We shall take a decision when the time comes. The urgency is not today. The problems are there and the urgency will arise in a year or two. Then if the Government comes to a decision after all the data laid before it that it is necessary to give an extension time for the scheduled castes and the scheduled tribes for reservation in the legislatures, then a bill will be drafted and that bill will be presented to this House and the other House. Then the hon. Members will be able to speak freely and give their opinion. I say personally for myself that the rate at which the weaker sections are progressing is not fast enough. We do not want to hide anything but then not money alone, not the policy which we have followed taking the inspiration from the Father of the Nation and laid down in our Constitution and living up to the best of our ability on the Governmental level, can solve the problems of the weaker sections of people unless there is an approach of the human heart and unless it is tackled on an individual level.

It was said here that unless this subject is tackled on an individual level and unless we make a yardstick to measure individuals who live in our society as to how far they are prepared to go then alone we can, with some confidence, come here and say that our policy has yielded results and that the money spent has borne fruit. But until then let us all put our shoulders together as the hon. lady Member pointed out that if certain weakness in the weaker section itself have to be put right, then let us do so. Let us build hostels. Let us have housing colonies in which all types of Harijans—and not only all types of Harijans, but non-scheduled castes also —will be represented to participate in the schemes so that amelioration of the scheduled castes and the scheduled tribes can be achieved in a time limit that we would like to envisage but we cannot envisage because of this human factor that stands in our way. I do not appreciate the manner in which,—I shall not say that criticism was laid at the Caste Hindus. It is there. It has come down from centuries. What are we going to do? It is for each one to

search his heart. It is for the Scheduled Castes themselves to search their hearts. But, we at least with a conviction say that we have made it our policy and we are doing our bit as much as we can for these people. The sooner untouchability goes and the sooner the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes come up to the level of civilisation or social growth or strata that we envisage, the better for us.

With these short comments on the debate, I now would urge on the hon. Mover to withdraw his Resolution. He knows the mind of the Government. He knows the urgency of the task. It is not he alone who feels the urgency. We also feel the urgency. We shall examine the issue and do justice to the nation.

Mr. Deputy-Speaker: May I know the reaction of the hon. Member?

श्री दीनबन्धु परमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के सामने मैं ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, वह इस भावना के साथ पेश किया कि आज देश में हरिजन और आदिवासी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको हर तरह से . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप क्या चाहते हैं, यह बतला दीजिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रेस करेंगे या विदड्रा ?

श्री दीनबन्धु परमार : सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया है कि हमारा जो रिजर्वेशन है, वह कायम रहेगा, उस को दृष्टि में रखते हुए मैं इस रेजोल्यूशन को वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी भी अपनी अमेंडमेंट वापस लेना चाहते हैं ?

श्री वाजपेयी : जी, हां ।

Mr. Deputy-Speaker: The Resolution is also withdrawn.

The amendment was, by leave, withdrawn.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION *RE*: RESETTLEMENT OF EAST PAKISTAN DISPLACED PERSONS

Mr. Deputy-Speaker: We have one minute for Shri Tangamani to move his Resolution.

Shri Tangamani (Madurai): Mr. Deputy-Speaker, I beg to move:

> "This House is of opinion that a Committee of Members of both the Houses be appointed to consider all questions relating to the rehabilitation of refugees from East Pakistan with a view to formulating a comprehensive plan for their speedy resettlement in gainful employment."

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

> "This House is of opinion that a Committee of Members of both the Houses be appointed to consider all questions relating to the rehabilitation of refugees from East Pakistan with a view to formulating a comprehensive plan for their speedy resettlement in gainful employment."

The hon. Member will continue next day.

17.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 17th March, 1958.